सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि
PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

" जब लोगों को उजाला नजर आने लगता है, तब वे भूल जाते हैं, कि अंधेरे में कौन साथ था... !"

अज्ञात...

वर्ष–01 अंक–163 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, गुरुवार 02 जुलाई 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए

बीएसपी में कथित लोहा चोरी पर विधानसभा तक पहुंची लड़ाई

विधायक रिकेश सीबीआई जांच की मांग को लेकर लाएंगे अशासकीय संकल्प

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र में वर्षों से चल रहे कथित लोहा चोरी के संगठित काले कारोबार के खिलाफ वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन ने अपनी मुहिम को अब छत्तीसगढ़ विधानसभा तक पहुंचा दिया है। विधायक सेन ने इस मामले में विधानसभा के नियम 117 के तहत अशासकीय संकल्प की सूचना विधानसभा सचिव को भेजते हुए केंद्र सरकार से पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

विधानसभा सचिवालय को भेजे गए इस अशासकीय संकल्प में विधायक रिकेश सेन ने कहा है कि भारत सरकार के उपक्रम सेल के अंतर्गत आने वाले भिलाई इस्पात संयंत्र में पिछले कई वर्षों से बड़े पैमाने पर कथित लोहा चोरी, वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक गड़बड़ियों की निष्पक्ष एवं व्यापक जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से कराई जानी चाहिए, ताकि राष्ट्रीय संपत्ति को हुए नुकसान का वास्तविक आंकलन हो सके और दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

विधायक सेन का कहना है कि यह मामला केवल लोहा चोरी तक सीमित नहीं है, बल्कि यह करोड़ों रुपये की राष्ट्रीय संपत्ति, जनता के धन और जवाबदेही से जुड़ा गंभीर विषय है। उन्होंने

कहा कि यदि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच होती है तो संगठित गिरोहों के साथ-साथ कथित व्हाइट कॉलर मददगारों, जिम्मेदार अधिकारियों और इस पूरे नेटवर्क को संरक्षण देने वाले प्रभावशाली लोगों की भूमिका भी सामने आएगी।

उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि वर्षों से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रत्येक व्यक्ति से जवाब मांगा जाए और उन्हें कानून के दायरे में लाया जाए। यह केवल चोरी का मामला नहीं, बल्कि देश की संपत्ति की सुरक्षा और जनता के विश्वास का प्रश्न है।

गौरतलब है कि हाल ही में विधायक रिकेश सेन ने सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाते हुए दावा किया था कि भिलाई इस्पात संयंत्र में करोड़ों रुपये के लोहे की चोरी और इस पूरे नेटवर्क को संरक्षण देने वालों के संबंध में उनके पास महत्वपूर्ण दस्तावेज और तथ्य हैं। इसके बाद उन्होंने संबंधित दस्तावेज विभिन्न स्तरों पर उपलब्ध कराते हुए कार्रवाई की मांग तेज कर दी है।

अशासकीय संकल्प में यह भी उल्लेख किया गया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र देश की महत्वपूर्ण औद्योगिक धरोहर और राष्ट्रीय संपत्ति है। यदि लंबे समय से हो रही कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच होती है तो इससे न केवल दोषियों पर कार्रवाई संभव होगी, बल्कि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाने के लिए भी मजबूत व्यवस्था विकसित की जा सकेगी।

विधायक रिकेश सेन का कहना है कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संपत्ति की सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए है।

बद्रीनारायण मीणा ने संभाला बस्तर रेंज के आईजी का पदभार

सुन्दरराज पट्टलिंगम एनआईए में बने आईजी, मिशन 2026 के लिए जताया आभार

नई दृष्टिबिंदु / जगदलपुर

बद्रीनारायण मीणा ने मंगलवार को औपचारिक रूप से बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक का पदभार ग्रहण कर लिया। उन्होंने सुन्दरराज पट्टलिंगम का स्थान लिया, जो अब भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए में पुलिस महानिरीक्षक की नई जिम्मेदारी संभालेंगे।

'मिशन 2026 को मिलेगी और गति' : पट्टलिंगम

निवर्तमान आईजी सुन्दरराज पट्टलिंगम ने मिशन 2026 के प्रभावी क्रियान्वयन में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मिशन 2026 भारत सरकार और छत्तीसगढ़ शासन की परिकल्पना है, जिसे बस्तर में स्थायी शांति, सुरक्षा और विकास के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि बद्रीनारायण मीणा के नेतृत्व में यह अभियान और गति पकड़ेगा। पट्टलिंगम ने शासन, पुलिस मुख्यालय, बस्तर की जनता, पुलिस बल, सुरक्षा बलों, नागरिक प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और मीडिया के प्रति आभार जताया। उन्होंने वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ संघर्ष में शहीद हुए जवानों और स्थानीय नागरिकों को श्रद्धांजलि भी दी।

'शांति और विकास के लिए करेंगे काम' : मीणा

नवनियुक्त आईजी बद्रीनारायण मीणा ने कहा कि वे पिछले वर्षों की उपलब्धियों को आगे बढ़ाते हुए सभी हितधारकों के साथ समन्वय में काम करेंगे। उन्होंने बस्तर में स्थायी शांति, सुरक्षा, विकास और जनविश्वास को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई।

पदभार ग्रहण समारोह में पहुंचे वरिष्ठ अधिकारी

पुलिस महानिरीक्षक, बस्तर रेंज कार्यालय में आयोजित समारोह में बस्तर के पुलिस अधीक्षक शलभ सिन्हा सहित बस्तर रेंज के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सुन्दरराज पट्टलिंगम ने मीणा का स्वागत करते हुए उन्हें सफल कार्यकाल के लिए शुभकामनाएं दीं। उन्होंने भरोसा जताया कि बस्तर पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी नए आईजी को भी वही समर्पण और सहयोग देंगे।

जीपीएस बंद कर फ्लू डस्ट की आड़ में करोड़ों का स्क्रैप पार

बीएसपी की सुरक्षा पर उठे सवाल, 250 टन लौह स्क्रैप चोरी मामले में 13 गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

भिलाई इस्पात संयंत्र से 250 टन लौह स्क्रैप चोरी के मामले ने बीएसपी की सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी तंत्र की पोल खोल दी है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि यह चोरी किसी एक व्यक्ति का काम नहीं बल्कि वर्षों से संगठित तरीके से चल रहा काला कारोबार था। मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

गोदाम से बरामदगी के बाद खुली परतें

मुखबिर की सूचना पर ग्राम अकलोरडीह स्थित एक गोदाम से भारी मात्रा में स्क्रैप बरामद होने के बाद जांच शुरू हुई। पुलिस को ऐसे कई तरीके मिले जिनसे वर्षों से संगठित तरीके से चल रहा काला कारोबार था। मामले में अब तक 13 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है।

अंदरूनी मिलीभगत का आरोप

वाहन संचालकों के मुताबिक माल ढुलाई से जुड़े कुछ ट्रांसपोर्टरों ने सुरक्षा की कमजोरियों का फायदा उठाया। आरोप है कि अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मिलीभगत से स्क्रैप बाहर निकाला जाता रहा। बताया जाता है कि कुछ ट्रांसपोर्टर चालकों को नियमित वेतन देते थे, जबकि कई चालक स्क्रैप चोरी की कमाई पर निर्भर थे। उन्हें निर्देश था कि डीजल, वेतन और खर्च चोरी के स्क्रैप की बिक्री से निकालें।

जीपीएस हटाकर बदलते थे रूट

गिरफ्तार ट्रांसपोर्टर संजय सिंह ने पूछताछ में पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी। वाहन खुर्सीपार रोलिंग मिल गेट से प्रवेश करते और वेट ब्रिज से गुजरकर फ्लू डस्ट लोड करते थे। इसके बाद जीपीएस निकाल दिया जाता था। वाहन तय मार्ग

छोड़कर स्क्रैप यार्ड पहुंचता, वहां स्क्रैप लोड कर ऊपर से फिर फ्लू डस्ट भर दी जाती थी। मुख्य वेट ब्रिज से बचते हुए वाहन उसी जगह लौटता जहां जीपीएस हटाया गया था। जीपीएस दोबारा लगाकर वाहन मुख्य गेट से बाहर निकल जाता था। पुलिस ने पूरे रूट का नक्शा साक्ष्य के रूप में सुरक्षित किया है।

चोरी के चौंकाने वाले तरीके

जांच में स्क्रैप चोरी के कई तरीके सामने आए हैं:

1. पहिया उतारकर: कुछ ट्रक 18 चक्कों के साथ प्लांट में जाते और 16 चक्कों के साथ बाहर आते थे। दो पहिये प्लांट में ही उतार दिए जाते और उनके बराबर वजन का करीब 400 किलो स्क्रैप लोड कर लिया जाता था। इससे वजन में अंतर नहीं आता था।

2. गुप्त चैंबर: कई वाहनों में गुप्त चैंबर बनाकर स्क्रैप छिपाकर ले जाया जाता था। आरोप है कि इनकी कभी प्रभावी जांच नहीं हुई।

3. फ्लू डस्ट की आड़: नीचे स्क्रैप भरकर ऊपर राख डाल दी जाती थी। इस तरीके से एक बार में 15 से 20 टन तक स्क्रैप बाहर ले जाने की बात सामने आई है।

जांच की गति पर सवाल, प्रभावशाली नाम भी दायरे में

शुरुआत में पुलिस इसे सामान्य चोरी मान रही थी, लेकिन पूछताछ और साक्ष्यों से स्पष्ट हुआ कि चोरी सुनियोजित थी। कई ट्रांसपोर्टर, बिचौलियों और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई है। सूत्रों के अनुसार शहर के कुछ प्रभावशाली नाम भी जांच के दायरे में हैं। लगातार गिरफ्तारियों के बाद अब जांच की गति धीमी पड़ने को लेकर सवाल उठ रहे हैं। एसपी सुखनंदन राठौर ने कहा कि जांच की गति धीमी नहीं पड़ी है। हर पहलू की रोज समीक्षा हो रही है। फरार आरोपियों के लिए अलग-अलग टीमें कार्रवाई में जुटी हैं।

मशाल रैली निकालकर मांगी निष्पक्ष जांच

250 टन स्क्रैप चोरी के विरोध में युवाओं ने सिविक सेंटर में मशाल रैली निकाली। उन्होंने निष्पक्ष जांच और सभी दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। सामाजिक कार्यकर्ता प्रशम दत्ता ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी कि निष्पक्ष कार्रवाई नहीं होने पर लोकतांत्रिक तरीके से व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा।

दुर्ग में 5 जुलाई को होगा 'संगीत मिलन और सम्मान समारोह'

वरिष्ठ पत्रकार संगीता मिश्रा होंगी मुख्य अतिथि, मृदुला रोजिन्दार और रश्मि अग्रवाल का होगा सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कोशिश स्टार म्यूजिकल एवं सोशल ग्रुप, दुर्ग द्वारा आगामी रविवार, 5 जुलाई 2026 को "संगीत मिलन एवं सम्मान समारोह" का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम लोक कला भवन, सिविल लाइन, कसारीडीह, दुर्ग में दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक चलेगा।

संगीता मिश्रा होंगी मुख्य अतिथि

समारोह की मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार सुश्री संगीता मिश्रा होंगी। कार्यक्रम में समाज सेवा और महिला नेतृत्व के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए लीनेस मृदुला रोजिन्दार, पास्ट मल्टीपल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लीनेस क्लब, तथा लीनेस रश्मि अग्रवाल, प्रांतीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़, ऑल इंडिया लीनेस ऑगनाइजेशन को विशेष रूप से सम्मानित किया जाएगा।

संगीत से सामाजिक समरसता का संदेश

आयोजन में शहर के संगीतकार, गायक-गायिकाएं, कलाकार, साहित्यकार और संगीत प्रेमी एक मंच पर जुटेंगे। ग्रुप के संरक्षक कैलाश जैन बरमेचा ने बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य संगीत के माध्यम से सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक चेतना और प्रतिभाओं के सम्मान की परंपरा को सशक्त करना है।

उन्होंने सभी संगीत प्रेमियों, कला अनुरागियों और शहरवासियों से अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने का आग्रह किया है।

अंबिकापुर में आसमानी आफत: ट्रक पर गिरी आकाशीय बिजली, धू-धू कर जला वाहन

अंबिकापुर। शहर में लगातार हो रही बारिश और गरज-चमक के बीच आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला। खरसिया रोड पर आकाशीय बिजली गिरने से एक ट्रक में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते पूरा ट्रक आग की लपटों से घिर गया और मौके पर अफरा-तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारिश के दौरान अचानक तेज गर्जना के साथ बिजली ट्रक पर गिरी। बिजली गिरते ही ट्रक से आग की तेज लपटें उठने लगीं और कुछ ही देर में पूरा वाहन आग की चपेट में आ गया। घटना के समय इलाके में तेज बारिश के साथ लगातार गरज-चमक हो रही थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि समय रहते आग बुझा ली गई, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई और बड़ा हादसा टल गया।

छत्तीसगढ़ को अंगदान में अग्रणी राज्य बनाने की पहल, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय को सौंपा 16 बिंदुओं का सुझाव-पत्र

सर्वधर्म सेवा संस्था ने की मांग : अंगदाताओं को मिले मरणोपरांत राजकीय सम्मान

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

छत्तीसगढ़ को अंगदान और देहदान में देश का अग्रणी राज्य बनाने की दिशा में सर्वधर्म सेवा संस्था, भिलाई ने पहल की है। संस्था के प्रतिनिधिमंडल ने संरक्षक इंद्रजीत सिंह छोटू भईया के मार्गदर्शन में मंगलवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की।

जन-आंदोलन बनाने का आग्रह

प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को 16 बिंदुओं का विस्तृत सुझाव-पत्र सौंपा और पूरे प्रदेश में अंगदान एवं देहदान को जन-आंदोलन के रूप में चलाने का आग्रह किया। संस्था ने मांग की कि अंगदान करने वाले दाताओं को मरणोपरांत राजकीय सम्मान प्रदान किया जाए, ताकि समाज में अंगदान के प्रति सम्मान और जागरूकता बढ़े।

'हजारों को मिलेगा नया जीवन'

संस्था का कहना है कि यदि शासन, चिकित्सा संस्थान, सामाजिक संगठन और आमजन मिलकर काम करें तो छत्तीसगढ़ हजारों लोगों को नया जीवन देने में सफल होगा। साथ ही अंगदान और देहदान के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य भी बन सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विषय को गंभीरता से सुनने के बाद सकारात्मक पहल का आश्वासन दिया। सर्वधर्म सेवा संस्था ने मुख्यमंत्री का आभार जताया है।

डॉक्टर्स डे पर समभाव समिति ने भिलाई के 31 चिकित्सकों का किया गया सम्मान

सेक्टर-9 अस्पताल में हुआ आयोजन, डॉ. रिजवी को घर पहुंचकर दी स्मृति-चिह्न

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस के अवसर पर समभाव सामाजिक समिति, भिलाई ने मंगलवार को जे.एल.एन. अस्पताल, सेक्टर-9 के सभागार में सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह में भिलाई इस्पात संयंत्र के 24 वरिष्ठ चिकित्सकों सहित कुल 31 डॉक्टरों को चिकित्सा सेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेक्टर-9 अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. उदय कुमार, समिति के संस्थापक-संरक्षक विमान भट्टाचार्य तथा श्रीमती बीना भट्टाचार्य रहे। सभी अतिथियों ने चिकित्सकों को स्मृति-चिह्न, उपहार, पुष्पगुच्छ और मिठाई भेंट कर समाज की ओर से कृतज्ञता व्यक्त की।

डॉ. विधान चंद्र राय को किया याद

कार्यक्रम का संचालन मंच संचालिका सुमन कनौजे ने किया। शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलन और महान चिकित्सक डॉ. विधान चंद्र राय के चित्र पर माल्यार्पण के साथ हुआ। भारत में प्रतिवर्ष उनके जन्मदिवस 1 जुलाई को राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस मनाया जाता है।

डॉ. रिजवी के निवास पर जाकर किया सम्मान

समारोह से पूर्व समिति के प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ चिकित्सक डॉ. रिजवी के नेहरू नगर स्थित निवास पर पहुंचकर उनका सम्मान किया और दीघर्कालीन चिकित्सा योगदान के लिए आभार जताया।

इन चिकित्सकों का हुआ सम्मान

सम्मानित होने वालों में डॉ. कौशलेन्द्र ठाकुर, डॉ. उदय कुमार, डॉ. पी. मर्सी, डॉ. अन्नपूर्णा, डॉ. नित्य एस. कुजूर, डॉ. त्रिनाथ दास, डॉ. वी.के. बंसल, डॉ. सम्बिता पांडा समेत सेक्टर-9 अस्पताल के 24 डॉक्टर

शामिल रहे। इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री शासकीय चिकित्सालय सुपेला के पूर्व प्रभारी डॉ. के. गोपीनाथ, स्पर्श हॉस्पिटल के डॉ. अरविंद प्रकाश सावंत, डॉ. टिलेश खुसरो, शासकीय चिकित्सालय दुर्ग की डॉ. तृप्ति तिवारी और श्री नारायणा हास्पिटल रायपुर की डॉ. लीना सिंह को भी सम्मानित किया गया।

'चिकित्सक समाज में आशा का संचार करते हैं'

'आवाज-24 न्यूज' के संवाददाता पाथर्जीत पाल ने डॉ. उदय कुमार का साक्षात्कार लिया। उन्होंने कहा कि चिकित्सक केवल रोगों का उपचार नहीं करते, बल्कि सेवा और समर्पण से समाज में आशा और विश्वास का संचार करते हैं। उनका सम्मान करना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कार्यक्रम में समिति अध्यक्ष पिलेश कुमार ने समिति के कार्यो की जानकारी दी। अंत में कवि गोविंद पाल ने सभी का आभार जताया। उन्होंने सीएमओ डॉ. उदय कुमार के विशेष सहयोग के लिए समिति की ओर से धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में सुनीता पाण्डेय का विशेष सहयोग रहा।

खास खबर

कलेक्टर ने नशा मुक्ति केंद्र का किया निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने सुपेला स्थित कल्याणी सोशल वेलफेयर एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र का निरीक्षण कर उपचार, परामर्श एवं पुनर्वास संबंधी व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने केंद्र में भर्ती मरीजों से चर्चा कर उन्हें उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, उपचार एवं काउंसलिंग की जानकारी ली। कलेक्टर ने केंद्र के संचालक अजय कल्याणी को भोजन, दवाइयों की उपलब्धता, सुरक्षा व्यवस्था तथा चिकित्सकीय सेवाओं की समीक्षा करते हुए सभी

आवश्यक सुविधाएं गुणवत्तापूर्ण ढंग से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नशा मुक्ति केंद्र केवल उपचार का स्थान नहीं, बल्कि नशे की लत से जूझ रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने मरीजों के पुनर्वास पर विशेष ध्यान देने की बात कही। संचालक अजय कल्याणी ने बताया कि केंद्र में मरीजों को सकारात्मक वातावरण के साथ नियमित काउंसलिंग, योग, व्यायाम, मेडिटेशन एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वे स्वस्थ एवं सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। उन्होंने बताया कि मरीजों को सामान्यतः एक माह तक केंद्र में रखकर उपचार एवं पुनर्वास कराया जाता है। घर लौटने के बाद भी उनकी नियमित फॉलोअप काउंसलिंग की जाती है, ताकि वे दोबारा नशे की ओर न लौटें।

धनरूपी लक्ष्मी का उपयोग धर्म, शिक्षा, सेवा और जरूरतमंदों असहायों की मदद में करें तो हरि कृपा मिलेगी : डॉ. पाराशर

भिलाई। श्री शंकराचार्य मेडिकल कॉलेज, भिलाई परिसर में आयोजित सात दिवसीय श्रीमद्भागवत कथा महोत्सव का समापन सोमवार श्रद्धा, भक्ति एवं उत्साह के साथ हुआ। 23 जून से शुरू हुए ज्ञानयज्ञ में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लेकर कथा सुनी। कथा व्यास डॉ. श्याम सुंदर पाराशर महाराज (श्रीधाम वृंदावन) ने अंतिम दिन श्रीमद्भागवत का सार प्रस्तुत करते हुए मानव जीवन के आदर्श, मित्रता, दान, सेवा एवं भक्ति का प्रेरणादायी संदेश दिया। महाराज ने कहा कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण समस्त सृष्टि के माता-पिता हैं। लक्ष्मीजी के साथ हमारा संबंध माता या पुत्री के रूप में होना चाहिए। जब धन को सद्कार्यों, धर्म, सेवा और परोपकार में लगाया जाता है, तभी उसका वास्तविक सदुपयोग होता है।

उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धन को केवल भोग-विलास का साधन मानता है, वह कभी स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। रुक्मिणी विवाह प्रसंग पर उन्होंने श्रद्धालुओं से आह्वान किया कि अपने धनरूपी लक्ष्मी का उपयोग धर्म, शिक्षा, सेवा तथा गरीब, असहाय एवं जरूरतमंद लोगों की सहायता में करें। दरिद्र नारायण की सेवा ही भगवान की सच्ची आराधना है। सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए महाराज ने सच्ची मित्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि वास्तविक मित्र वही है जो अपने मित्र के कष्ट को बिना बताए समझे और उसकी सहायता करे।

जनशिकायत संबंधी आवेदनों का करें त्वरित निराकरण : कलेक्टर अभिजीत सिंह

पंचायतों में राजस्व प्रकरणों के पंजीयन का हो रिकार्ड दुरुस्ती

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कलेक्टर अभिजीत सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में अधिकारियों की बैठक में विभागवार समय-सीमा के लंबित आवेदनों की गहन समीक्षा की। साथ ही लंबित आवेदनों का निराकरण समयावधि में करने के निर्देश दिये। उन्होंने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, जन शिकायत पोर्टल के लंबित आवेदनों के निराकरण की जानकारी लेते हुए कहा कि जनशिकायत संबंधी आवेदनों का अधिकारी त्वरित निराकरण करना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर ने जनशिकायत से संबंधित आवेदन लंबित होने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अधिकारियों को कड़ी फटकार लगायी। कलेक्टर श्री सिंह ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत विभागों को प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली। साथ ही एल-1 अधिकारी को समय-सीमा के भीतर प्रकरण निराकृत करने कहा। विभागीय अधिकारियों ने सीएम हेल्पलाइन अंतर्गत तकनीकी दिक्कतों से अवगत कराया। कलेक्टर श्री सिंह ने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को उच्च स्तर पर आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये हैं।

कलेक्टर श्री सिंह ने ग्राम पंचायतों में राजस्व प्रकरण अविवादित, नामांतरण, बंटवारा पंजीयन की जानकारी ली। साथ ही पंचायत सचिवों द्वारा राजस्व प्रकरणों के पंजीयन उपरांत रिकार्ड दुरुस्ती पर जोर देते हुए एसएलआर को पंचायतों में पंजीकृत प्रकरणों के रिकार्ड दुरूस्ती कराने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि शासकीय प्रयोजन हेतु विभागों को भू-आबंटन के लंबित प्रकरण होने पर संबंधित विभाग राजस्व विभाग को प्रकरण प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें ताकि भू-आबंटन की कार्यवाही में प्रगति लायी जा सके। कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग में एनएचएम एवं अन्य पदों पर भर्ती प्रक्रिया की जानकारी ली। उन्होंने सीएमएचओ को एनएचएम भर्ती काउंसलिंग तिथि पश्चात उसी दिन नियुक्ति आदेश जारी करने के निर्देश दिये। इसके अलावा शेष अन्य पदों पर भी भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण कराने निर्देशित किया। कलेक्टर ने कहा कि जिले में अधोसंरचनात्मक निर्माण कार्यो को गति प्रदान करने विभागीय बेस लाइन सर्वे अंतर्गत नगरीय निकायों/जनपद पंचायतों से जानकारियां मंगायी जा रही है। संबंधित विभाग के अधिकारी अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त जानकारी मय हस्ताक्षर के साथ संबंधित निकायों/जनपद को उपलब्ध कराने निर्देशित करें।

बैठक में एडीएम वीरेन्द्र सिंह, जिला पंचायत के सीईओ बजरंग दुबे, अपर कलेक्टर श्रीमती योगिता देवांगन, नगर निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त सुमीत अग्रवाल, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, एसडीएम दुर्ग हरवंश सिंह मिरी, एसडीएम पाटन लवकेश ध्रुव सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

बाबा धाम धनोरा में धूमधाम से मनाया जाएगा गुरुपूर्णिमा पर्व

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

बाबा दरबार पावन धाम धनोरा दुर्ग में हर साल की भांति इस वर्ष भी स्व. परमानंद कठोलिया की स्मृति में श्रद्धांजलि एवं पुण्य तिथि मनाने का निर्णय लिया गया। दरबार के लक्ष्मण बाबा ने बताया कि इस वर्ष 2 अगस्त रविवार को सुबह 10 बजे से रात्रि 9 बजे तक गुरु पूणिर्मा एवं अतिथी स्वागत का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्य अतिथि पद्म मंमता चन्दाकर एवं प्रेम चन्दाकर फिल्म निर्देशक एवं निर्माता विशेष अतिथि दुष्यंत हरमुख, रंग झरोखा संस्थान रिंकी देवांगन, लोक गायिका स्वर कोकिला कविता वासनिक, सुश्री हिमानी वासनिक, कु कनक साहू बाल कलाकार, लोकगायिका तृषा साहू, लोकगायिका एवं टोमन वर्मा जस जगराता गायक का आगमन एवं शाम 5 बजे से सुश्री हिमानी वासनिक के मंडली द्वारा भरथरी का आयोजन एवं शाम 4 बजे से प्रसाद खिचड़ी वितरण किया जाएगा यह कार्यक्रम जुगल किशोर कठोलिया एवं बाबा दरबार पावन धाम धनोरा एवं दरबार में आने वाले भक्त गण के द्वारा किया जा रहा है।

बैठक में मुख्य रूप से शामिल रहे दरबार के लक्ष्मण बाबा, नंद पंडा, विनोद कुमार साहू, राजू यादव, मनसुखा साहू, मनोज पटेल, गुलाब साहू, योगेश साहू, राजू देशमुख, भोलू, खिलेशवर साहू, सुंदर सपरे, चन्द्रकांत देवांगन, एमलाल देवांगन, कल्याण देवांगन, ललित साहू, रोशन साहू, डॉ धनेशवर साहू, डोरे लाल साहू, मंच संचालक बबलू, गज्जू रायपुरीहा, जीवराखन ठेकेदार, बाबू लाल साहू, योगेश साहू, दिनेश साहू, मुनना गंधर्व, सुनील पेटर, दिनेश यादव, रामु यादव, ओमकार साहू, टीकम, गुमान साहू, तोमन गजपाल, उमेश साहू, वासुदेव स्प्रे, पूर्व उपसरपंच कुंभकरण पटेल, हेमंत साहू, भजन गायक मारियल साहू, कुणाल साहू, कुंजलाल साहू, श्रीमती बबिता साहू, ललिता यादव, सुनीता साहू, मितानिन कौशिलया सेन, रुखमणि साहू, पावर्ती मंडलिन, प्रभा साहू, देवश्री, अंजु देवांगन, संगीता सपरे, उपसरपंच टिकेशवरी साहू, लक्ष्मी साहू, हितेश पटेल, नीरा साहू, मुंगा सपरे, गीता देवांगन, मंजू साहू, पुष्पा देवांगन, कु. पुजा साहू, कु. वेदू साहू, कु. नेहा साहू, कु. सुरुचि, छोटी, कु. डिंपल साहू, कु. विनना साहू आदि श्रद्धालुओं ने बड़ी संख्या में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यह जानकारी दरबार प्रति निधी चंन्द्र कांत कोसरे एवं कुंज लाल साहू ने दी।

किसानों को मिली राहत, पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी मिलेगा यूरिया खाद

किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर ही खरीफ 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

राज्य सरकार के फैसले से जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। खरीफ 2026 के दौरान किसानों को यूरिया की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सहकारी क्षेत्र में यूरिया वितरण संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया है। शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार यूरिया की वतर्मान पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए पूर्व में जारी कुछ प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया है। नए निर्देशों के अनुसार अब पात्र किसानों को खरीफ 2025 में प्राप्त यूरिया की मात्रा के बराबर ही खरीफ 2026 में भी यूरिया उपलब्ध कराया जाएगा।

उप संचालक कृषि संदीप भोई ने बताया कि किसानों को यह उर्वरक एकमुश्त अथवा संबंधित सहकारी समिति में उपलब्ध स्टॉक के आधार पर चरणबद्ध तरीके से वितरित किया जाएगा। सहकारी समिति मे यूरिया की अल्प उपलब्धता की स्थिति में कृषक की पत्रातानुसार यदि यूरिया प्राप्त किया जाना शेष हो, तो शेष मात्रा समिति में यूरिया उपलब्ध होने पर प्राप्त की जा सकेगी।

जिले में किसान भाईयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने हेतु कलेक्टर अभिजित सिंह के मार्गदर्शन में सतत भंडारण एवं वितरण की कार्यवाही की जा रही है। जिले में खरीफ 2026 हेतु कुल 67880 मीट्रिक टन उर्वरक

वितरण का लक्ष्य रखा गया है। वतर्मान में सहकारी एवं निजी क्षेत्र को मिलाकर जिले में 22688 मीट्रिक टन यूरिया, 4376 मीट्रिक टन डीएपी, 11725 मीट्रिक टन एनपीके, 5901 मीट्रिक टन एमओपी तथा 11067 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कुल 55757 मीट्रिक टन उर्वरक भंडारण किया गया है एवं सेवा सहकारी समितियों एवं निजी विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को लगातार उर्वरकों का वितरण किया जा रहा है। अब तक 11986 मीट्रिक टन यूरिया, 3431 मीट्रिक टन डीएपी, 5371 मीट्रिक टन एनपीके, 3612 मीट्रिक टन एमओपी तथा 7161 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कुल 31561 मि.टन उर्वरक का वितरण किया जा चुका है तथा वतर्मान में जिले में 10701 मीट्रिक टन यूरिया, 946 मीट्रिक टन डीएपी, 6354 मीट्रिक टन एनपीके, 2289 मीट्रिक टन एमओपी तथा 3906 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फॉस्फेट कुल 24196 मि.टन उर्वरक शेष है। जिले में उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता है तथा किसी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।

जिले के सभी किसान भाइयों से अपील की गई है कि फसलों के बेहतर उत्पादन एवं भूमि कि सेहत के लिए वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित संतुलित खाद का ही उपयोग करें। किसान भाई अपनी पात्रता के अनुसार निकटतम सहकारी समिति से संपर्क कर सुगमतापूर्वक यूरिया का उठाव कर सकते हैं।

कुथरेल में धूमधाम से मनाया गया सदगुरु संत कबीर साहेब प्रकटोत्सव

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

ग्राम कुथरेल में मानिकपुरी पनिका समाज द्वारा सदगुरु संत कबीर साहेब प्रकटोत्सव समारोह का भव्य आयोजन किया गया। इस पावन अवसर पर दुर्ग ग्रामीण के विधायक एवं छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष (कैबिनेट मंत्री दर्जा) ललित चंद्राकर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए।

विधायक ललित चंद्राकर ने सर्वप्रथम संत कबीर साहेब जी के तैल चित्र पर पूजा अचर्ना कर आशीर्वाद प्राप्त किया और समस्त समाजजन को कबीर प्रकट उत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। कार्यक्रम में भजन-कीर्तन, सत्संग एवं कबीर वाणी का पाठ किया गया। समाज के वरिष्ठजनों का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक ललित चंद्राकर ने कहा कि सद्गुरु संत कबीर

साहेब की वाणी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने जाति-पाति, ऊंच-नीच और आडंबरों से ऊपर उठकर मानवता का संदेश दिया। कबीर की साखी और दोहे समाज को जोड़ने का काम करते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें सत्य, प्रेम और सद्भाव के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं।

श्री चंद्राकर ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ की माटी संत कबीर की कमर्भूमि रही है। यहां की परंपरा में कबीरपंथ रचा-बसा है। राज्य सरकार भी संत परंपरा और समाज के उत्थान के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने समाज के युवाओं से आह्वान किया कि वे कबीर जी के आदर्शों को जीवन में अपनाकर शिक्षा, स्वरोजगार और सामाजिक समरसता के क्षेत्र में आगे बढ़ें। विधायक ने पनिका समाज द्वारा सामाजिक एकता और संस्कृति के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों की सराहना की और हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

समारोह में प्रमुख रूप से जनपद सभापति लोमश चंद्राकर, पनिका समाज अध्यक्ष नरेन्द्र दास, महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मानिकपुरी, कोषाध्यक्ष तामेश्वर दास, सचिव मनीष दास, चेतन दास, राम दास, पेमेन्द्र दास, झरना दास, ताम्रध्वज मानिकपुरी, चंद्राकर समाज अध्यक्ष डॉ. परमेश्वर चंद्राकर, देशमुख समाज अध्यक्ष गोविंद देशमुख सहित बड़ी संख्या में मानिकपुरी पनिका समाज, चंद्राकर समाज, देशमुख समाज एवं सर्व समाज के लोग उपस्थित रहे।

भारतीय स्टेट बैंक के 71वें स्थापना दिवस पर सेक्टर-1 भिलाई में रक्तदान शिविर आयोजित

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

46 यूनिट रक्त संग्रहित

भारतीय स्टेट बैंक के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को भारतीय स्टेट बैंक, सेक्टर-1 भिलाई द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्धता सुनिश्चित करना रहा। यह आयोजन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला दुर्ग डॉ. मनोज दानी, जिला चिकित्सालय दुर्ग के सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. आशीषन मिंज तथा जिला चिकित्सालय दुर्ग ब्लड बैंक प्रभारी डॉ. संतराम चुरेंद्र के मार्गदर्शन एवं दिशा-निर्देश में संपन्न हुआ।

रक्तदान शिविर में भारतीय स्टेट बैंक सेक्टर-1 भिलाई के क्षेत्रीय प्रबंधक अनिल कुमार यादव, प्रबंधक मानव संसाधन सौरोदीप हालदार, मुख्य प्रबंधक वरुण शुक्ला, श्रीमती सुष्मिता बोस सहित बैंक के अधिकारियों एवं कमर्चारियों का सराहनीय योगदान रहा। शिविर के दौरान कुल 46 यूनिट रक्त संग्रहित किया गया। आयोजन में रेडक्रास सोसायटी के प्रबंध कायर्कारिणी सदस्य एवं जीवन दीप समिति के आजीवन सदस्य दिलीप सिंह ठाकुर तथा मानद सदस्य प्रशांत डोंगावकर की विशेष सहभागिता एवं प्रेरणादायी सहयोग उल्लेखनीय रहा।

कार्यक्रम के दौरान डॉ. विजय वर्मा, डॉ. वैष्णवी आडिल, काउंसलर टी. एस. एंथोनी, स्टाफ नर्स तरूणा रावत, ब्लड बैंक सुपरवाइजर रूपेश सर्पे, सीनियर लैब टेक्नीशियन महेंद्र चंद्राकर, मधुसूदन देवांगन, भूपेश दिल्लीवार, तरुण महिलागें, हिमांशु चंद्राकर एवं अशोक मानिकपुरी सहित अन्य उपस्थित रहे। समारोह के अंत में सभी अतिथियों ने रक्तदाताओं को साधुवाद देते हुए उनके योगदान की सराहना की और कहा कि रक्तदान मानवता की सेवा का श्रेष्ठ माध्यम है। रक्तदाताओं ने स्वैच्छिक भागीदारी निभाकर समाज के प्रति अपने दायित्व का उदाहरण प्रस्तुत किया।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के संकल्प से कुनकुरी में आकार ले रहा आधुनिक नालंदा परिसर

24 घंटे खुली रहने वाली लाइब्रेरी में डिजिटल संसाधन, ऑक्सी रीडिंग जोन और प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष व्यवस्था

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जशपुर जिले के कुनकुरी स्थित सलियाटोली में 4.37 करोड़ रुपये की लागत से 250 सीटर सर्वसुविधायुक्त नालंदा परिसर का निर्माण तेजी से किया जा रहा है। यह परिसर क्षेत्र के विद्यार्थियों को आधुनिक, तकनीकी आधारित और गुणवत्तापूर्ण अध्ययन का वातावरण उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री श्री साय ने 21 जून 2025 को इस परियोजना का भूमिपूजन किया था।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं को उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में नालंदा परिसर विकसित किए जा रहे हैं। जशपुर जिले में जिला मुख्यालय जशपुर और कुनकुरी के सलियाटोली में ऐसे आधुनिक

परिसर बनाए जा रहे हैं, जहां विद्यार्थियों को विशाल पुस्तकालय, डिजिटल संसाधन और तकनीकी सुविधाओं से युक्त अध्ययन वातावरण मिलेगा। यह परिसर विद्यार्थियों के लिए 24 घंटे और सप्ताह के सातों दिन खुला रहेगा।

नालंदा परिसर में इंडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के अध्ययन की सुविधा उपलब्ध होगी। विद्यार्थी प्राकृतिक वातावरण के बीच विकसित ऑक्सी रीडिंग जोन में भी अध्ययन कर सकेंगे। परिसर को पर्यावरण अनुकूल अवधारणा के साथ विकसित किया जा रहा है, जहां सौर ऊर्जा आधारित प्रकाश व्यवस्था, ऊर्जा दक्ष भवन डिजाइन तथा 50 से अधिक देशी पौधों का रोपण किया जाएगा।

ज्ञान के साथ स्वास्थ्य और नवाचार पर भी रहेगा फोकस

परिसर में विद्यार्थियों की समग्र आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए यूथ टावर, स्पोर्ट्स कोर्ट, कैफेटेरिया, एटीएम और हेल्थ जोन जैसी सुविधाएं भी विकसित की जाएंगी। भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप इसे स्वायत्त एवं स्ववित्तपोषित संचालन मॉडल पर विकसित किया जा रहा है।

डिजिटल लाइब्रेरी और अत्याधुनिक प्रबंधन प्रणाली

नालंदा परिसर की लाइब्रेरी में 50 हजार से अधिक पुस्तकें उपलब्ध होंगी। इसके साथ डिजिटल लाइब्रेरी, हाई-स्पीड वाई-फाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की विशेष पुस्तकें तथा ई-लर्निंग संसाधनों की सुविधा भी रहेगी। परिसर में आरएफआईडी आधारित प्रवेश प्रणाली, बायोमेट्रिक पहचान, आरएफआईडी से पुस्तकों की ट्रैकिंग तथा आधुनिक सॉफ्टवेयर आधारित पुस्तक प्रबंधन व्यवस्था लागू की जाएगी।

यह नालंदा परिसर जशपुर जिले के युवाओं को अपने क्षेत्र में ही महानगरों के समान आधुनिक अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं और उच्च शिक्षा की बेहतर तैयारी का सशक्त केंद्र बनेगा।

खास खबर

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए रायपुर में राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, जनभागीदारी और सर्कुलर इकोनॉमी पर विशेषज्ञों ने किया मंथन

छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के क्षेत्रीय कार्यालय, रायपुर द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के उद्देश्य से न्यू सर्किट हाउस, सिविल लाइंस, रायपुर में एक दिवसीय राज्य स्तरीय कायर्शाला का आयोजन किया गया। कायर्शाला में ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक प्रबंधन, स्रोत स्तर पर कचरा पृथक्करण, संग्रहण, प्रसंस्करण एवं पर्यावरण अनुकूल निस्तारण सहित नियमों के विभिन्न प्रावधानों पर विस्तार से चर्चा की गई।

कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा ने कहा कि स्वच्छ एवं स्वस्थ शहरों के निर्माण के लिए ठोस अपशिष्ट का वैज्ञानिक प्रबंधन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कचरे के पृथक्करण, पुनर्चक्रण तथा वैज्ञानिक प्रबंधन में नागरिकों, स्थानीय निकायों और संस्थानों की सक्रिय भागीदारी पर बल देते हुए इसे जनआंदोलन बनाने का आह्वान किया। क्षेत्रीय अधिकारी पी.के. रबड़े ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रावधानों, विभिन्न विभागों की जिम्मेदारियों तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नियम केवल कानूनी प्रावधान नहीं, बल्कि सर्कुलर इकोनॉमी की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं, जिनका उद्देश्य कचरे को संसाधन के रूप में उपयोग कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि नए नियमों के तहत बल्क वेस्ट जेनरेटरों को अपने द्वारा उत्पन्न कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन की जिम्मेदारी स्वयं निभानी होगी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ ने स्वच्छता दीदियों के माध्यम से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण का सफल मॉडल विकसित किया है। साथ ही बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के सीमेंट संयंत्रों में नगरीय ठोस अपशिष्ट से तैयार आर.डी.एफ. (त्मनिम क्मतपअमक थ्नमस) का ईंधन के रूप में उपयोग कर कचरे के वैज्ञानिक निस्तारण और वैकल्पिक ऊर्जा के उपयोग का सफल उदाहरण प्रस्तुत किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल नियम-2026 के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी हितधारकों को तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है तथा सामूहिक प्रयासों से रायपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ को जीरो वेस्ट स्टेट बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। कार्यशाला में राज्य सलाहकार श्रीमती मोनिका सिंह एवं पुरुषोत्तम पंडा (स्वच्छ भारत मिशन), कार्यपालन अभियंता योगेश कुमार कडू, मुख्य रसायनज्ञ श्रीमती नीलिमा सोनकर तथा सहायक अभियंता प्रवीण कुमार नाग ने पॉवरपॉइंट प्रस्तुतीकरण के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026, वैज्ञानिक कचरा प्रबंधन, स्रोत स्तर पर पृथक्करण, प्रसंस्करण तथा व्यावहारिक क्रियान्वयन की विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में शहरी एवं ग्रामीण निकायों के प्रतिनिधि, उद्योग प्रतिनिधि, बल्क वेस्ट जेनरेटर, ईको क्लब समन्वयक, स्वच्छ भारत मिशन के अधिकारी तथा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के अधिकारी-कमर्चारी सहित लगभग 250 प्रतिभागियों ने सहभागिता की। कायर्शाला का उद्देश्य ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम-2026 के प्रति व्यापक जागरूकता बढ़ाना, विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना तथा पर्यावरण संरक्षण के लिए वैज्ञानिक एवं प्रभावी कचरा प्रबंधन को बढ़ावा देना था।

नैनो यूरिया से स्वस्थ मिट्टी और टिकाऊ खेती की ओर बढ़ रहे किसान

रायपुर। कृषि में आधुनिक तकनीकों को अपनाने की दिशा में जिले के किसान लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में ग्राम बावा गठोली के कृषक संपद दास मानिकपुरी ने नैनो यूरिया का उपयोग कर खेती में सकारात्मक अनुभव साझा किए हैं। संपद दास मानिकपुरी ने बताया कि स्वस्थ मिट्टी, संतुलित पोषण और टिकाऊ कृषि की दिशा में नैनो उर्वरक एक महत्वपूर्ण पहल साबित हो रहे हैं। नैनो यूरिया के उपयोग से पोषक तत्वों का बेहतर प्रबंधन संभव हो रहा है, जिससे फसल को आवश्यक पोषण समय पर प्राप्त होता है। साथ ही यह मिट्टी की जैविक सक्रियता को बनाए रखने तथा पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने में भी सहायक है। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग के मार्गदर्शन में नैनो यूरिया का उपयोग करने से आधुनिक एवं वैज्ञानिक खेती को बढ़ावा मिला है। यह तकनीक किसानों के लिए एक उपयोगी विकल्प बनकर उभर रही है, जिससे खेती अधिक टिकाऊ और प्रभावी बन सकती है। मानिकपुरी ने जिले के अन्य किसानों से भी वैज्ञानिक सलाह के अनुरूप नैनो उर्वरकों का उपयोग करने की अपील करते हुए कहा कि आधुनिक कृषि तकनीकों को अपनाकर बेहतर उत्पादन के साथ-साथ मिट्टी की उर्वरता को भी लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। नैनो उर्वरक अपनाएं, स्वस्थ मिट्टी और हरित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।

केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू और उप मुख्यमंत्री साव ने 10 करोड़ के कार्यों का किया भूमिपूजन

उप मुख्यमंत्री ने मुक्तिधाम के लिए 50 लाख और सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ की घोषणा की

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू तथा उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बिलासपुर के मंगला स्थित माता चौरा में लगभग 10 करोड़ रुपये के विकास कार्यों का भूमिपूजन किया। इनमें क्षेत्र के विकास को गति देने वाले कई कार्य शामिल हैं। इन कार्यों से मंगला सहित आसपास के क्षेत्रों में नागरिक सुविधाएं बेहतर होंगी और क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी। विधायक सुशांत शुक्ला, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष राजा पांडे, महापौर श्रीमती पूजा विधानी और जिला पंचायत के अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी भी कार्यक्रम में शामिल हुए।

केंद्रीय आवास और शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र और राज्य सरकार विकास को मिशन के रूप में आगे बढ़ा रही है। डबल इंजन सरकार के समन्वित प्रयासों से विकास कार्यों को गति मिली है। अब केवल भूमिपूजन नहीं, बल्कि समयबद्ध तरीके से विकास कार्यों का लोकार्पण भी सुनिश्चित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिलासपुर सहित पूरे छत्तीसगढ़ में अधोसंरचना विकास को नई गति मिली है। सड़क, रेल, पेयजल और शहरी विकास के क्षेत्र में लगातार बड़े कार्य हो रहे हैं। बिलासपुर को महत्वपूर्ण परियोजनाओं की स्वीकृति मिली है। रेलवे के विस्तार, स्टेशनों के उन्नयन और अन्य विकास कार्यों से क्षेत्र के लोगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

उप मुख्यमंत्री तथा बिलासपुर जिले के प्रभारी मंत्री अरुण साव ने अपने संबोधन में कहा कि प्रदेश सरकार विकास कार्यों को सवोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछले दो वर्षों में बिलासपुर नगर निगम को 437 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। आने वाले

समय में शहर और आसपास के क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा, ताकि नागरिकों को पानी की समस्या का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में किसी प्रकार की कमी नहीं आने दी जाएगी और जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री श्री साव ने मंगला मुक्तिधाम के लिए 50 लाख रुपये तथा सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 1 करोड़ रुपये देने की घोषणा की।

कार्यक्रम को विधायक सुशांत शुक्ला ने भी संबोधित किया। बिलासपुर नगर निगम के कमिश्नर प्रकाश सर्वे, दीपक सिंह, मोहित जायसवाल और पिछड़ा वर्ग आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ. सोमनाथ यादव सहित जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में कार्यक्रम में उपस्थित थे।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बस्तर संभाग की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बुधवार को बस्तर कलेक्टोरेट के प्रेरणा सभाकक्ष में शिक्षा विभाग की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक लेकर विभागीय योजनाओं एवं शैक्षणिक गतिविधियों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर एवं प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश देते हुए कहा कि बस्तर के समग्र विकास में शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने अंदरूनी क्षेत्रों के स्कूलों को पुनर्जीवित करने, विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने, शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने तथा विद्यालयों में बेहतर शैक्षणिक वातावरण विकसित करने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने प्राथमिक स्तर पर गणित, हिंदी और अंग्रेजी की मजबूत आधारशिला तैयार करने के लिए कैलेंडरवार, शालावार एवं विषयवार समय-सारणी के अनुसार पढ़ाई कराने तथा नियमित रिवीजन टेस्ट आयोजित करने के निर्देश दिए।

बैठक में शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, संचालक ऋतुराज रघुवंशी, कलेक्टर आकाश छिकारा, जिला पंचायत सीईओ प्रतीक जैन, संभागीय संयुक्त संचालक एच.आर. सोम सहित सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी, डीएमसी, बीईओ एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। समीक्षा के दौरान आधार बेस ऐप के माध्यम से कार्यालयीन अधिकारियों-कमर्चारियों की उपस्थिति तथा वीएसके ऐप में शिक्षकों की ऑनलाइन उपस्थिति की जानकारी ली गई। ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं करने वाले अधिकारियों एवं कमर्चारियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने तथा नेटवर्क विहीन स्कूलों की सूची कलेक्टर

के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। शिक्षा मंत्री ने अन्य विभागों में पदस्थ शिक्षा विभाग के अधिकारियों-कमर्चारियों को मूल पदस्थापना पर वापस भेजने संबंधी निर्देशों के पालन की भी समीक्षा की।

श्री यादव ने बसाहटवार प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति, नए विद्यालयों की आवश्यकता, बंद स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने की काययीजना, बोर्ड एवं वार्षिक परीक्षा परिणामों की समीक्षा करते हुए पोटा केबिनों में अंतरजिला विद्यार्थियों को प्रवेश देने के निर्देश दिए। उन्होंने वार्षिक परीक्षा में बेहतर परिणाम के लिए पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों के आधार पर विषयवार यूनिट टेस्ट एवं तिमाही परीक्षाएं आयोजित करने तथा कमजोर विद्यालयों के प्राचार्यों की बैठक लेकर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जिला एवं विकासखंड शिक्षा अधिकारियों को दिए। बैठक में विद्यार्थियों के नामांकन, उपस्थिति, ड्रॉपआउट की स्थिति, शिक्षकों की उपलब्धता, रिक्त एवं युक्तियुक्तकरण किए गए पदों, स्वामी विवेकानंद उत्कृष्ट विद्यालयों की कार्ययोजना एवं गैप एनालिसिस की प्रगति की भी समीक्षा की गई। छात्रवृत्ति, गणवेश, पाठ्यपुस्तक वितरण, सरस्वती सायकल योजना, मध्यान्ह एवं न्यौता भोजन, निर्माण कार्यों तथा शासन की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

समक्षः- नोटरी, सिविल जिला बेमेतरा (छ.ग.)
॥ शपथ पत्र ॥

मैं श्रीमती ज्योति देवी उम्र लगभग 52 वर्ष पति श्री अमरचंद गिलड़ा पता दुर्ग बेमेतरा, तह. व जिला बेमेतरा (छ.ग.) का हूं। जो निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूँ :-

यह कि मेरे द्वारा मौजा कोबिया प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कोबिया, तह. व जिला बेमेतरा (छ. ग.) में स्थित ख.नं. 2100, 2106, 2108, 2109/1 रकबा क्रमशः 0.170, 0.049, 0.032, 0.049 हे. भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता श्रीमती हवाबाई पति श्री रहीम भाई से दिनांक 27.08.2011 को प्राप्त की हूं। यह कि मुझे विक्रेता श्रीमती हवाबाई पति श्री रहीम भाई ने मौजा कोबिया प.ह.नं. 27, रा.नि.मं. कोबिया, तह. एवं जिला बेमेतरा (छ.ग.) में स्थित ख.नं. 2100, 2106, 2108, 2109/1 रकबा क्रमशः 0.170, 0.049, 0.032, 0.049 हे. भूमि को दिनांक 20.10.2008 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से श्री देवचरण पिता श्री सियाराम से क्रय किया था, जिसका ग्रंथ क्र. 6922 द.क्र. 1922 है। उपरोक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र की मूल प्रति विक्रेता द्वारा मुझे प्रदान की गयी थी जो गुम हो गयी है जिसे मेरे द्वारा खोज किए जाने पर भी मूल प्रति मुझे नहीं मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2007 जिसका ग्रंथ क्र. 6922 द.क्र. 1922 की मूल प्रति मिलने की संभावना नहीं है। यह कि उपरोक्त संपत्ति की किसी भी अंश के संबंध में कोई व्यवहार वाद सिविल प्रकरण अपना अथवा स्वत्व हस्तांतरण संबंधी प्रकरण किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है। यह संपत्ति हर प्रकार के विवादों से मुक्त है। जिसका एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी मैं ही हूं। **शपथकर्ता**

॥ सत्यापन ॥

मैं श्री रूपेश कुमार गिलड़ा उम्र लगभग 38 वर्ष पिता श्री रानीदान गिलड़ा पता दुर्ग रोड बेमेतरा, तह. व जिला बेमेतरा (छ.ग.) सत्यापित करती हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य व्यक्तिगत ज्ञान एवं जानकारी से सत्य व सही है। जिसे आज दिनांक 30.06.2026 को बेमेतरा में पढ़कर, समझकर व सही होना जानकर हस्ताक्षरित कर सत्यापित करती हूँ। **ज्योति गिलड़ा**
सत्यापनकर्ता

समक्षः- नोटरी, सिविल जिला बेमेतरा (छ.ग.)
॥ शपथ पत्र ॥

मैं श्री रूपेश कुमार गिलड़ा उम्र लगभग 38 वर्ष पिता श्री रानीदान गिलड़ा पता दुर्ग रोड बेमेतरा, तह. व जिला बेमेतरा (छ.ग.) का हूं। जो निम्नानुसार शपथ पूर्वक कथन करता हूँ :-

यह कि मेरे द्वारा मौजा मटका प.ह.नं. 36, रा.नि.मं. व तह. बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में स्थित ख.नं. 222/2, 226 रकबा 0.33, 0.23 हे. भूमि को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रेता राजबीर सिंह पिता श्री देवराज सिंह से दिनांक 29.07.2025 को प्राप्त किया है।

यह कि मुझे विक्रेता श्री राजबीर सिंह पिता श्री देवराज सिंह ने मौजा मटका प.ह.नं. 36, रा.नि.मं. व तह. बेमेतरा, जिला बेमेतरा (छ.ग.) में स्थित ख.नं. 222/2, 226 रकबा 0.33, 0.23 हे. भूमि को दिनांक 12.01.2007 को पंजीबद्ध विक्रय पत्र के माध्यम से श्री महाबीर पिता श्री रूपचंद एवं भगवान पिता श्री फत्ते सिंह से क्रय किया था, जिसका ग्रंथ क्र. 6622 द.क्र. 3036 है।

उपरोक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र की मूल प्रति विक्रेता द्वारा मुझे प्रदान की गयी थी जो गुम हो गयी है जिसे मेरे द्वारा खोज किए जाने पर भी मूल प्रति मुझे नही मिली। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त पंजीबद्ध विक्रय पत्र दिनांक 12.01.2007 की मूल प्रति मिलने की संभावना नहीं है।

यह कि उपरोक्त संपत्ति की किसी भी अंश के संबंध में कोई व्यवहार वाद सिविल प्रकरण अपना अथवा स्वत्व हस्तांतरण संबंधी प्रकरण किसी भी न्यायालय में लंबित नही है। यह संपत्ति हर प्रकार के विवादों से मुक्त है। जिसका एकमात्र स्वामी एवं आधिपत्यधारी मै ही हूं। **शपथकर्ता**

॥ सत्यापन ॥

मैं श्री रूपेश कुमार गिलड़ा उम्र लगभग 38 वर्ष पिता श्री रानीदान गिलड़ा पता दुर्ग रोड बेमेतरा, तह. व जिला बेमेतरा (छ.ग.) सत्यापित करता हूं कि उक्त शपथ पत्र में वर्णित तथ्य व्यक्तिगत ज्ञान एवं जानकारी से सत्य व सही है। जिसे आज दिनांक 30.06.2026 को बेमेतरा में पढ़कर, समझकर व सही होना जानकर हस्ताक्षरित कर सत्यापित करता हूँ। **रूपेश गिलड़ा**
सत्यापनकर्ता

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई नगर, तहसील व जिला दुर्ग

-:: ईश्तहार ::-

(रा.प्र.क्रं./...../अ-27/वर्ष 2025-26)

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुरेश कुमार सिंह आ./ध.प. स्व. जगन्नाथ सिंह निवासी लक्ष्मी नगर चौक रिसाली द्वारा ग्राम कोहका प.ह.नं. 45 रा.नि.मं. कोहका तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि ख. नं. 1908 रकबा 0.0400 हे. भूमि सुरेश कुमार सिंह वैगरह के नाम पर शामिलात खाते में दर्ज है। उपर वर्णित भूमि को खातेदारों द्वारा आपसी सहमती के अनुसार खाता विभाजन किये जाने हेतु आवेदनमय दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है।

अतः उपरोक्त संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 22/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 25.06.2026 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय के मुहर से जारी किया गया है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202606101000180

विषयः- ब-121
मामले की श्रेणीः- राजस्व
सनः- 2025-2026
कुरूद प.ह.न. 00045 [(हे0)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार-जय किशन आहूजा
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक : जयकिशन आहूजा पिता/पति/विभाग-स्व. सावलदास आहूजा पता-भिलाई द्वारा ग्राम-कोहका प.ह.न. 19 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. 7565/1रकबा 0.013 हे. भूमि आवेदक एवं अन्य के नाम पर दर्ज है। उक्त भूमि की ऋण पुस्तिका कहीं गुम हो जाने के कारन डुप्लीकेट ऋण पुस्तिका प्राप्त किये जाने बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है।

उपरोक्त भूमि पर जिस किसी भी व्यक्ति-संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई दिनांक 08/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने माध्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25/06/2026 को जारी किया जाता है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक : 202606101000179

विषयः- अ-6 अ
मामले की श्रेणीः- राजस्व
सनः- 2025-2026
कुरूद प.ह.न. 00046 [(हे0)]
पक्षकारों का विवरण - आवेदक पक्षकार-लिखन देशमुख,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक लिखन देशमुख पिता/पति/विभाग-मोतीलाल देशमुख पता-भिलाई द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.न. 46 रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग की भूमि ख.न. 177/2 का टू. रकबा 0.003 हे./367.50 वर्गफीट को आवेदक द्वारा क्रय किया जाकर ऋण पुस्तिका प्राप्त कर लिया गया है किन्तु उक्त भूमि वतर्मान पटवारी अभिलेख में आवेदक के स्थान हिना अंजुम का नाम प्रदर्शित हो रहा है। जिसे त्रुटी सुधार किये जाने हेतु न्यायालय में आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है।

उपरोक्त भूमि का नामान्तरण किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति संस्था को उजर दावा हो तो सुनवाई तिथि दिनांक 06/07/2026 तक या उसके पूर्व स्वयं या अपने मान्य अधिवक्तागण के साथ उपस्थित होकर अपना आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 25/06/2026 को जारी किया जाता है।

अतिरिक्त तहसीलदार
भिलाई नगर

न्यायालय तहसीलदार अहिवारा जिला दुर्ग (छ.ग.)

रा.प्र.क्र. / 202606104000067/अ-6/वर्ष 2025-26
ग्राम बानबरद प.ह.नं. 06

// उद्घोषणा //

एतद् द्वारा सर्व साधारण को सूचित किया जाता है, कि आवेदिका श्रीबन्ती मन्ना पति सुनील कुमार मन्ना जाति बंगाली निवासी नंदिनी नगर अहिवारा तहसील अहिवारा जिला दुर्ग (छ.ग.) के द्वारा आवेदन पेश किया गया है कि ग्राम बानबरद, प.ह.नं. 06 तहसील अहिवारा जिला दुर्ग में स्थित भूमि खसरा नंबर 232/1 रकबा 0.07 को भूमिस्वामी / विक्रेता राधिका देवी पति कपिलदेव सिंह निवासी रूवाबांधा तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) से पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 05.01.2001 के माध्यम से क्रय किया गया है। किन्तु अपरिहार्य कारणों से नामांतरण नही करवा पाये थे। उक्त पंजीकृत विक्रय विलेख के आधार पर क्रय की गई भूमि पर क्रेता के नाम पर नामांतरण दर्ज करने हेतु निवेदन किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव इस आवेदन के संबंध में विधिक आपत्तियों / दावा रखने वाला जिस व्यक्ति / संस्था को कोई आपत्ति, दावा हो तो स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से इस न्यायालय में पेशी दिनांक 15/07/2026 को या उसके पूर्व कार्यालयीन दिवस को लिखित में आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पर कोई विचार नही किया जावेगा।

यह ईश्तहार आज दिनांक 23/06/2026 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय के सील-मुहर से जारी किया गया है।

पेशी दिनांकः 15/07/2026
जारी दिनांकः 23/06/2025
मुहर

तहसीलदार
अहिवारा, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

संपादकीय

अतिक्रमण है तो कानूनन हटाया ही जाएगा

गलत काम करने वाले भी जानते हैं कि वह आज गलत काम कर रहे हैं तो कल इस गलत काम के कारण उनको या उनके परिवार को नुकसान हो सकता है, तकलीफ हो सकती है। फिर भी गलत काम करने वाले गलत काम करते हैं तो उनको होने वाली तकलीफ,आंसू देख सुनकर जाहिर तौर पर बुरा तो लगता है कि इनके साथ ऐसा नहीं किया जाना चाहिए लेकिन यह भी ख्याल आता है कि इनको तो मालूम था वह जो काम कर रहे हैं उसके कारण एक दिन उनको तकलीफ तो होगी फिर यह काम इन्होंने किया है तो कहा जा सकता है कि यह आंसू व यह तकलीफ तो इनकी नियति थी और इसके लिए वह भी जिम्मेदार हैं ।नकटी गांव के वे लोग ऐसे हैं जिनके अवैध कब्जे में बने मकान सोमवार को तोड़े गए हैं ।साय सरकार के सुशासन पर सवालिया निशान लगाने वाले कह रहे हैं कि क्या यही सुशासन है ।ऐसे लोगों से सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सुशासन तब ही होता है जब कोई भी कहीं भी शासकीय जमीन पर कब्जा कर ले और सरकार जमीन को उनके नाम कर दे। ऐसा सुशासन तो छत्तीसगढ़ तो कांग्रेस व विपक्ष शासित किसी राज्य में नहीं होगा। जहां भी अवैध कब्जा किया गया है, वहां तो कभी न कभी कानूनन हटाया ही जाएगा। नकटी में यही किया गया है।

जिनके अवैध कब्जे में बनाए गए मकान तोड़े गए हैं, उनका कहना है कि जल्दी में यह काम किया गया है इससे उनको सामान हटाने का मौका नहीं मिला,उनको परेशानी हुई, उनके बच्चों को परेशानी हुई ।यह सच नहीं है नकटी गांव के लोगों को क्या राजधानी के तमाम लोगों को मालूम है कि अवैध कब्जे हटाने का नोटिस तो कुछ दिन पहले ही सभी घरों में लगा दिया गया था कि आप लोग अपना घर खाली कर दें क्योंकि तय समय के बाद मकान तोड़े जाएंगे। इसके बाद सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने बैठक में कहा था कि पुनर्वास की व्यवस्था किए बिना इनको न हटाया जाए तो इनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की गई उसके बाद अवैध कब्जे में बने 77 मकान तोड़े गए हैं ।ऐसा भी नहीं है कि प्रशासन ने यूं ही लोगों के मकान तोड़ दिए हैं और उनका मकसद गरीब व मजदूर लोगों को परेशान करना था ।राजस्व विभाग के मुताबिक तो यह कार्रवाई न्यायालय के अप्रैल 2025 के अनुसार की गई है। इस हिसाब से देखा जाए तो अवैध कब्जे हटाने के लिए प्रशासन ने बहुत समय दिया है ।अवैध कब्जाधारियों को अवैध कब्जा करने के बाद भी उम्मीद थी कि शायद उनके विरोध प्रदर्शन,कांग्रेस के विरोध के चलते अवैध कब्जा छोड़ दिया जाए। उनके मकान न तोड़े जाएं। यह उम्मीद बेकार की उम्मीद थी क्योंकि मकान अवैध कब्जे में बने थे इसलिए तोड़े गए। कांग्रेस सरकार के सम ? भी तोड़े जाते तो इसी कारण तोड़े जाते कि मकान सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाए गए हैं, इसलिए तोड़े गए हैं।

सरकार भाजपा की रहे या कांग्रेस की रहे,सरकारी जमीन पर कब्जा कोई भी करे उसे कानून हटाया ही जाता है भले ही वहां मकान बनाकर लोग रह रहे हैं। अवैध कब्जा हटाने का कानून तो वही रहता है सरकार किसी की भी रहे लेकिन राजनीति करनेवाला बदल जाते हैं ।कांग्रेस सरकार में रहती है तो भाजपा नेता उनके साथ खड़े हो जाते हैं कि अरे अरे आप लोगों के साथ सरकार ने बड़ा अन्याय कर दिया है। आज भाजपा सरकार है तो अतिक्रमणकारियों के साथ कांग्रेस नेता आकर खड़े हो गए हैं ।जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली की कडी निंदा कर रहे हैं,कुछ कह रहे हैं कि कितनी मेहनत से मकान बनाया था,असंवेदनशील सरकार ने तोड़ दिया ।बिना मानवीय दृष्टिकोण अपनाए और प्रभावित परिवारों के सम्मानजनक पुनर्वास किया बिना ऐसी कार्रवाई तो गरीबों के साथ अन्याय है। कोई कह रहा है कि भाजपा सरकार गरीबों के दर्द व आंसुओं को समझने में विफल है। इस तरह की कार्रवाई से भाजपा का दोहरा चरित्र उजागर हो गया है। कोई कांग्रेस नेता कह रहा है कि यदि सरकार गरीबों के साथ न्याय नहीं करती है तो कांग्रेस आंदोलन करेगी।

ऐसे समय मे एक पक्ष जब सरकार को अन्यायी बताने का प्रयास करता है तो सरकार के लिए भी जरूरी हो जाता है कि वह राज्य के लोगों को बताए कि वह सुशासन वाली सरकार है,सुशासन ही उसका लक्ष्य है और वह जो करती है कि राज्य में सुशासन व जनता व राज्यहित में करती है ।कलेक्टर साहब का बताना जरूरी हो जाता है कि जो कुछ किया गया है वह नियमानुसार किया गया है। इसलिए गौरव सिंह ने बयान दिया है कि नकटी गांव की भूमि शासकीय परियोजना के लिए आरक्षित थी,यहा कब्जा करने वाले परिवारों को नियमानुसार आवास उपलब्ध कराया गया है। कार्रवाई के दौरान कई भावुक दृश्य लोगों ने देखा,भावुक लोगों को यह न लगे कि वाकई सरकार ने लोगों को दुख पहुंचाने का काम किया है,विधायक अ ?ुज शर्मा ने बताया कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा,सरकार विस्थापितों की पूरी चिंता करेगी ।विस्थापितों के लिए जहां उनकी व्यवस्था की गई है, वहां प्रशासन ने भोजन सहित सभी व्यवस्था की है।

कोई भी सरकार रहे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे तो होते रहते हैं ।ऐसा नहीं है कि भाजपा के समय होते हैं और कांग्रेस के समय नहीं होते हैं। इसी तरह अवैध कब्जे सरकार किसी की रहे वह हटाए जाते हैं और हटाने का एक ही तरीका होता है। कोई उसे अन्याय कह सकता है तो कोई उसे नियमानुसार की गई कार्रवाई कह सकता है। अवैध कब्जे होते क्यों हैं इसकी कई वजहें हो सकती हैं कि कुछ लोग आदतन अवैध कब्जे करने वाले होते हैं, अवैध कब्जा करते हैं और किसी को बेच भी देते हैं। कुछ लोग इस उम्मीद में कब्जा कर लेते हैं कि उसका कब्जा बाद हो सकता है कि नियमित कर दिया जाए। जैसे अवैध नल, अवैध कालोनी को नियमित किया जाता है ।कई लोग इसलिए कब्जा कर लेते हैं कि अभी तो कर लेते हैं बाद में जो होगा देखा जाएगा ।सराकर व जिला प्रशासन की लापरवाही भी एक कारण होती है ।सरकारी जमीन पर कहीं बोर्ड नहीं लगा होता कि यह सरकारी जमीन पर इस पर कब्जा करना मना है,कब्जा करने पर क्या कार्रवाई की जाएगी। सरकार को अवैध कब्जे का पता तब चलता है जब कोई परियोजना बनाती है ।यह तो मजाक जैसा लगता है कि अवैध कब्जे और सरकारी जमीन पर सरकारी योजना के तहत सरकार के पैसे से इंदिरा आवास व पीएम आवास तक बन जाता है। बाद में उसे तोड़ भी दिया जाता है। दुनिया में कुछ शाश्वत नियम होते हैं वह बदलते नहीं है इसी तरह सरकारी,नजूल की जमीन है तो कब्जा तो होगा ही,यह नियम भी शाश्वत है कोई भी सरकार आए नहीं बदलता है और यह भी शाश्वत नियम है कि अवैध कब्जा है तो उसे कानूनन हटाया जाएगा।

वायु प्रदूषण के साथ ओजोन प्रदूषण की चुनौती

ललित गर्ग

राजधानी दिल्ली वर्षों से वायु प्रदूषण की भयावह समस्या से जूझती रही है। हर सर्दी में धुंध की मोटी चादर, जहरीली हवा और दमघोंटू वातावरण राष्ट्रीय चिंता का विषय बनते हैं। अब तक इस संकट की चर्चा मुख्यत: पीएम 2 .5, पीएम 10, पराली और वाहनों के धुएँ तक सीमित रही, लेकिन अब एक नया और अधिक खतरनाक खतरा तेजी से उभरकर सामने आया है–भूतलीय (ग्राउंड लेवल) ओजोन प्रदूषण। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की हालिया रिपोर्ट ने स्पष्ट किया है कि दिल्ली–एनसीआर ही नहीं, जयपुर, चंडीगढ़ और अहमदाबाद जैसे शहर भी ओजोन प्रदूषण की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। यह प्रदूषण दिखाई नहीं देता, लेकिन इसके दुष्प्रभाव धीरे–धीरे मानव जीवन, कृषि और पर्यावरण को भीतर तक बीमार कर रहे हैं। विडम्बना यह है कि प्रदूषण जैसे गंभीर विषय को भी अक्सर राजनीतिक आरोप–प्रत्यारोप तक सीमित कर दिया जाता है। कभी किसानों की पराली को संपूर्ण दोषी ठहरा दिया जाता है तो कभी केवल वाहनों को। जबकि वास्तविकता कहीं अधिक व्यापक है। यदि समस्या की जड़ तक पहुँचना है तो अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध औद्योगीकरण, ऊर्जा उपभोग की वतर्मान व्यवस्था और विकास के मौजूदा मॉडल पर गंभीर पुनर्विर्चार करना होगा।

दिल्ली आज केवल देश की राजधानी नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा प्रदूषण हॉटस्पॉट भी बन चुकी है। गर्मियों में बढ़ते तापमान, तेज धूप और वाहनों एवं उद्योगों से निकलने वाली नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों की रासायनिक प्रतिक्रिया से भूतलीय ओजोन बनती है। यह वही ओजोन नहीं है जो वायुमंडल की ऊपरी परत में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। धरातल पर बनने वाली ओजोन एक विषैली गैस है, जो फेफड़ों की कार्यक्षमता कम करती है, दमा के रोगियों की स्थिति बिगाड़ती है, आँखों में जलन पैदा करती है तथा हृदय रोगों का जोखिम बढ़ाती है। आज दिल्ली–एनसीआर में बड़ी संख्या में लोग सांस लेने में कठिनाई, एलर्जी और अस्थमा जैसी समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जिनमें ओजोन प्रदूषण की भूमिका लगातार बढ़ रही है। दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन, नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, चार्जिंग स्टेशन विकसित करने की योजना और पुराने प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध तरीके से हटाने जैसे निर्णय निश्चित रूप से सकारात्मक हैं। यदि इन योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन होता है तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण नियंत्रण की दिशा में सार्थक परिवर्तन देखने को मिल सकता है। लेकिन केवल वाहन नीति से समस्या का समाधान संभव नहीं है।

वास्तविक संकट अनियोजित शहरीकरण का है। पिछले दो दशकों में दिल्ली और उससे लगे क्षेत्रों में जिस तेजी से खेत, तालाब और हरित क्षेत्र कंक्रीट के जंगलों में बदले हैं, उसने प्राकृतिक संतुलन को गहरा आघात पहुँचाया है। जहाँ कभी वर्षा का पानी धरती में समा जाता था, वहाँ अब सीमेंट और डामर की सतह है। पारंपरिक जलस्रोत मिट गए, पेड़ों की संख्या घटी और गर्मी बढ़ती गई। यही कारण है कि शहरों का तापमान आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में कई डिग्री अधिक रहने लगा है। यही अतिरिक्त गर्मी ओजोन बनने की प्रक्रिया को और तेज करती है। आज महानगरों का विस्तार विकास का प्रतीक माना जाता है, लेकिन यह विकास प्रकृति की कीमत पर हो रहा है। शहरों को सड़कें चाहिए, बिजली चाहिए, आवास चाहिए, उद्योग चाहिए। इन सबके लिए खेत समाप्त हो रहे हैं, जंगल कट रहे हैं और जलस्रोत नष्ट हो रहे हैं। परिणामस्वरूप प्रदूषण केवल हवा तक सीमित नहीं रहा, बल्कि जल, मिट्टी और जैव विविधता भी प्रभावित हो रही है। विकास की यह दिशा अंततः मानव जीवन के विरुद्ध खड़ी दिखाई देती है। दिल्ली में निजी वाहनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता और गुणवत्ता अभी भी इतनी प्रभावी नहीं हो सकी कि लोग निजी वाहनों का त्याग करें। इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना स्वागतयोग्य है, किंतु यह भी ध्यान रखना होगा कि बिजली यदि कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से आएगी तो प्रदूषण केवल एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होगा। इसलिए स्वच्छ ऊर्जा, सौर ऊर्जा और हरित परिवहन को समानांतर गति से बढ़ाना आवश्यक है।

ओजोन प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करता है। वैज्ञानिक अध्ययनों में पाया गया है कि ओजोन फसलों की प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को प्रभावित कर उत्पादन घटा देती है। ऐसे समय में जब जलवायु परिवर्तन, अनिश्चित मानसून और बढ़ती गर्मी पहले ही किसानों के सामने बड़ी चुनौती बने हुए हैं, ओजोन प्रदूषण कृषि संकट को और गहरा कर सकता है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक शहरों में वायु गुणवत्ता सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, किंतु अब समय आ गया है कि इसकी रणनीति का विस्तार किया जाए। केवल पार्टिकुलेट मैटर पर ध्यान देने के बजाय ओजोन जैसे द्वितीयक प्रदूषकों की निगरानी, वैज्ञानिक अध्ययन और नियंत्रण पर भी समान बल देना होगा। वायु गुणवत्ता निगरानी तंत्र को अधिक व्यापक, आधुनिक और पारदर्शी बनाना होगा।

समस्या के समाधान में नागरिकों की भूमिका भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कचरा जलाना, निर्माण कार्यों से उड़ने वाली धूल, खुले में ईंधन जलाना, प्लास्टिक और औद्योगिक कचरे का अनुचित निस्तारण जैसी आदतों में परिवर्तन लाना होगा। अधिक से अधिक सार्वजनिक परिवहन का उपयोग, साइकिल और पैदल चलने की संस्कृति को बढ़ावा देना होगा। शहरों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण, हरित पट्टियों का विकास और पारंपरिक जलस्रोतों का पुनर्जीवन भी प्रदूषण नियंत्रण की प्रभावी रणनीति का हिस्सा होना चाहिए। वायु प्रदूषण केवल पर्यावरणीय संकट नहीं, बल्कि आर्थिक और सामाजिक संकट भी है। बढ़ती बीमारियाँ स्वास्थ्य व्यवस्था पर बोझ डालती हैं, कार्यक्षमता घटाती हैं और करोड़ों रुपये की आर्थिक हानि का कारण बनती हैं। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि प्रदूषण बच्चों और युवाओं के भविष्य को प्रभावित कर रहा है। यदि आज निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका कहीं अधिक गंभीर मूल्य चुकाना पड़ेगा।

दिल्ली सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम स्वागतयोग्य हैं और उनसे सकारात्मक परिणामों की आशा की जा सकती है, किंतु यह तभी संभव होगा जब केंद्र, राज्य, स्थानीय निकाय, उद्योग, वैज्ञानिक समुदाय और नागरिक समाज मिलकर समन्वित प्रयास करें। प्रदूषण किसी एक सरकार, एक मौसम या एक कारण की समस्या नहीं है। यह हमारे विकास मॉडल, जीवनशैली और पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण का परिणाम है। आज आवश्यकता दोषारोपण की नहीं, बल्कि दूरदर्शी नीति और सामूहिक उत्तरदायित्व की है। यदि हम स्वच्छ हवा चाहते हैं तो केवल प्रदूषण कम करने की योजनाएँ नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ संतुलित विकास की नई संस्कृति विकसित करनी होगी। अन्यथा ओजोन जैसी अदृश्य गैसें हमारे शहरों को धीरे–धीरे बीमार करती रहेंगी और विकास का यह मॉडल स्वयं मानव सभ्यता के लिए सबसे बड़ा संकट बन जाएगा।

इस्लाम धर्म अपनाने वालों को नहीं मिलेगा आरक्षण

प्रमोद भार्गव

उच्च न्यायालय मद्रास ने तमिलनाडू सरकार के उस अहम् आदेष को रदद् कर दिया, जिसके तहत हिंदू धर्म के पिछड़े, अति पिछड़े या अनुसूचित जाति वर्ग के लोग इस्लाम अपनाने के बाद भी पिछड़े वर्ग मुस्लिम का जाति प्रमाण पत्र ले सकते थे। सरकारी नौकरी और षिक्षा में आरक्षण पा लेने की इस सुविधा को न्यायालय ने दो टूक षब्दों में असंवैधानिक माना है। अदालत ने कहा कि धर्म बदलने वाला व्यक्ति पिछड़ा वर्ग मुस्लिम का दर्जा मांगने का अधिकार नहीं रखता है। क्योंकि मुस्लिम समाज में भी अलग–अलग समुदाय और वर्ग होते हैं, परंतु उनकी पहचान जन्म से तय होती है न कि धर्म परिवर्तन से ? अदालत ने यह भी कहा कि इस्लामिक उपदेशक और ईसाई मिशनरियां सदियों से यह प्रचार करती आई हैं कि उनके धर्मों में सामाजिक समानता है, जबकि हिंदू धर्म में जाती व्यवस्था एक बुनियादी विसंगति है। अतएव धर्म परिवर्तन के लिए ऐसा रुख अपनाने के बाद यह कहना बेमानी है कि इस्लाम में भी ऊंच–नीच या वगर्भेद है। हमारी राय में कुछ मुस्लिम समुदायों को पिछड़ा और कुछ को अगड़ा मानना कुरान की शिक्षाओं के खिलाफ है। दरअसल इस्लाम एक ऐसा समाज बनाना चाहता है, जिसमें सब का दर्जा एक समान रहे। यह ऐतिहासिक फैसला न्यायामूर्ति जीआर स्वामीनाथन और पीबी बालाजी की पीठ ले दिया है।

इस मामले में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने तमिलनाडू सरकार के तीन मार्च 2024 के आदेष को आधार बनाया था। जिसमें आरक्षित श्रेणियों से धर्मांतरित लोगों को तमिलनाडू में अधिसूचित सात पिछडे वर्ग के मुस्लिम समूहों में से एक से संबंधित होने का सामुदायिक प्रमाण–पत्र जारी किया जा सकता था। सरकार ने अपने आदेष में यह प्रविधान किया था कि अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग या डी–नोटिफाइड समुदायों से आने वाले व्यक्ति यदि इस्लाम धर्म अपनाते हैं तो उन्हें पिछड़ा वर्ग मुस्लिम की क्षेणी में आरक्षण का लाभ दिया जा सकता है। इस सिलसिले में सरकार का तर्क था कि धर्म परिवर्तन करने वाले लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे और सामाजिक संतुलन बना रहेगा। किंतु अदालत ने कहा कि आरक्षण का आधार धर्म नहीं बल्कि, सामाजिक और षैक्षिक पिछड़ापन है।

इसी से मिलती–जुलती प्रकृति के एक एक मामले में फैसला देते हुए सवीच्च न्यायालय कह चुका है कि बिना किसी वास्तविक आस्था के केवल आरक्षण के लाभ हेतु किया गया धर्म परिवर्तन संविधान के साथ धोखाधड़ी है। सी सेल्वरानी की याचिका पर 26 नवंबर 2024 को फैसला सुनाते हुए, मद्रास उच्च न्यायालय के 24 नवंबर के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें ईसाई धर्म अपना चुकी एक महिला को अनुसूचित जाति प्रमाण–पत्र देने से इंकार कर दिया गया था। महिला ने बाद में आरक्षण के तहत रोजगार का लाभ प्राप्त करने के लिए हिंदू होने का दावा किया था। लेकिन इस पीठ ने फैसले में साफ किया कि कोई व्यक्ति किसी अन्य धर्म को तभी अपनाता है, जब वह वास्तव में उसके सिद्धांतों और धर्म आधारित आध्यात्मिक विचारों से प्रेरित होता है। यदि धर्म परिवर्तन का मकसद दूसरे धर्म में वास्तविक आस्था होने की बजाय आरक्षण का लाभ प्राप्त करना है तो इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि ऐसी गलत इच्छा रखने वाले लोगों को आरक्षण का लाभ देने से आरक्षण नीति के सामाजिक व्यवहार को क्षति पहुंचेगी। बावजूद सेल्वरानी हिंदू होने का दावा करती है और नौकरी के लिए अनुसूचित जाति का प्रमाण–पत्र मांगती है, तब यह दोहरा दावा अस्वीकार्य है। साफ है, वह ईसाई धर्म अपनाने के बावजूद एक हिंदू के रूप में अपनी पहचान नहीं बनाए रख सकती हैं।

संविधान के तीसरे अनुच्छेद, अनुसूचित जाति आदेश 1950 जिसे प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के नाम से भी जाना जाता है, के अनुसार केवल हिंदू धर्म का पालन करने वालों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को अनुसूचित जाति की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। इसी तारतम्य में पिछले पचास सालों से दलित ईसाई और दलित मुसलमान संघर्षरत रहते हुए हिंदू अनुसूचित जातियों को दिए जाने वाले अधिकारों की मांग करते चले आ रहे हैं। वतर्मान में मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई और बौद्ध ही अल्पसंख्यक दायरे में आते हैं। जबकि जैन, बहाई और कुछ दूसरे धर्म–समुदाय भी अल्पसंख्यक दर्जा हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जैन समुदाय केन्द्र द्वारा अधिसूचित सूची में नहीं है। इसमें भाषाई अल्पसंख्यकों को अधिसूचित किया गया है, धार्मिक अल्पसंख्यकों को नहीं। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के मुताबिक जैन समुदाय को भी अल्पसंख्यक माना गया है। परंतु इन्हें अधिसूचित करने का अधिकार राज्यों को है, केंद्र को नहीं। इन्हीं वजहों से आतंकवाद के चलते अपनी ही पुश्तैनी जमीन से बेदखल कश्मीरी पंडित अल्पसंख्यक के दायरे में नहीं आ पा रहे हैं। मध्यप्रदेश में दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार के दौरान जैन धर्मावलंबियों को भी अल्पसंख्यक दर्जा दिया था, लेकिन अल्पसंख्यकों को दी जाने वाली सुविधाओं से ये आज भी वंचित हैं।

संविधान के अनुच्छेद–342 में धर्म परिवर्तन के संबंध में अनुच्छेद–341 जैसे प्रावधान में लोच है। 341 में स्पष्ट है कि अनुसूचित जाति (एससी) के लोग धर्म परिवर्तन करेंगे तो उनका आरक्षण समाप्त हो जाएगा। इस कारण यह वर्ग धर्मांतरण से बचा हुआ है। जबकि 342 के अंतर्गत संविधान निर्माताओं ने जनजातियों के आदि मत और पुरखों की पारंपरिक सांस्कृतिक आस्था को बनाए रखने के लिए व्यवस्था की थी कि अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार अधिसूचित किया जाएगा। यह आदेश राष्ट्रपति द्वारा राज्य की अनुशंसा पर दिया जाता है। इस आदेश के लागू होने पर उल्लेखित अनुसूचित जनजातियों के लिए संविधान सम्मत आरक्षण के अधिकार प्राप्त होते हैं। इस आदेश के लागू होने के उपरांत भी इसमें संशोधन का अधिकार संसद को प्राप्त है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1956 में एक संशोधन विधेयक द्वारा अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण पर प्रतिबंध के लिए प्रावधान किया गया था कि यदि इस जाति का कोई व्यक्ति ईसाई या मुस्लिम धर्म स्वीकारता है तो उसे आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। किंतु यह विधेयक पारित नहीं हो पाया है। अनुच्छेद 341 के अनुसार अनुसूचित जातियों के वही लोग आरक्षण के दायरे में हैं, जो भारतीय धर्म हिन्दू, बौद्ध और सिख अपनाने वाले हैं। गोया, अनुच्छेद–342 में 341 जैसे प्रावधान हो जाते हैं, तो अनुसूचित जनजातियों में धर्मांतरण की समस्या पर स्वाभाविक रूप से अंकुश लग जाएगा।

राज्यसभा में भाजपा सांसद जीवीएल नरसिम्हा राव द्वारा पुछे गए एक सवाल के जबाव में पूर्व विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा था कि ह्यअनुसूचित जाति एवं जनजाति के जिन लोगों ने इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लिया है, वे आरक्षण के लाभ का दावा नहीं कर सकते हैं। यही नहीं ये लोग सरकारी नौकरियों के साथ–साथ संसद और विधानसभा के लिए आरक्षित सीटों पर भी चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल हिन्दू, सिख और बौद्ध मत को मानने वाले लोग ही अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ने की पात्रता रखेंगे। इन्हीं लोगों को सरकारी नौकरियों की पात्रता रहेगी ।ह्य उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया था कि ह्यइस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्यों को संसद या विधानसभा चुनाव लड़ने से रोकने के लिए जन–प्रतिनिधित्व अधिनियम में भी संशोधन की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि हिंदुत्व को मानने वाले और इस्लाम या ईसाई धर्म अपना चुके लोगों के बीच अधिनियम में पहले से ही स्पष्ट विभाजन रेखांकित है ।ह्य इस बयान से साफ हुआ था कि इस्लाम और ईसाई धर्म अपनाने वाले दलित और बृहद हिंदू धर्म के तहत आने वाले दलितों के बीच अंतर साफ है। यदि कालांतर में कायर्पालिका और विधायिका में बिना किसी बाधा के इस बयान पर अमल की प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो हिंदुओं में धर्म परिवर्तन थमने का सिलसिला शुरू हो जाता और इससे राष्ट्रवाद को मजबूती मिलती। क्योंकि ज्यादातर ईसाई व इस्लामिक संस्थाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य के बहाने हिंदुत्व और भारतीय राष्ट्रवाद की जड़ों में मट्ठा घोलने के लिए विदेशी धन मिलता है।

2006 में केंद्र में जब संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार थी, तब संविधान में 93वां संशोधन कर अनुच्छेद–15 में नया खंड–5 जोड़कर स्पष्ट किया गया था कि सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकेंगे। लेकिन ये प्रावधान अल्पसंख्यक संस्थाओं को छोड़कर सभी निजी संस्थाओं पर लागू होंगे। चाहे उन्हें सरकारी अनुदान प्राप्त होता हो। यह प्रावधान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद–15 के खंड 3 व 4 के क्रम में ही किया गया था। इससे भी साफ होता है कि इन जातियों के जो लोग ईसाई या इस्लामिक संस्थाओं अर्थात अल्पसंख्यक संस्थाओं में धर्म परिवर्तित कर शिक्षा लेते हैं, उन्हें अनुदान की पात्रता नहीं होगी। साफ है, अब तक धर्म परिवर्तन कर अनुसूचित जातियों के अधिकार को छीनकर हकमारी कर रहे लोगों को वास्तव में आरक्षण के लाभ की पात्रता नहीं है। अतएव अनुसूचित जातियों के परिप्रेक्ष्य में न्यायालय के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि ईसाई या इस्लाम धर्मावलंबी बने अनुसूचित जाति के लोग केवल नौकरी के लिए फिर से धर्म परिवर्तन कर हिंदू नहीं बन सकते है। यह उपाय आरक्षण के मूल उद्देष्य के विरुद्ध होने के साथ संविधान के साथ धोखाधड़ी है। यह उपाय आरक्षण नीति के मौलिक समाजिक लक्ष्यों को कमजोर करता है। अतएव ऐसे उपाय हाषिए पर पड़े समुदायों के उत्थान के उद्देष्य के तहत आरक्षण नीतियों की मूल भावना के विपरीत हैं।

क्या कांग्रेस बदल रही है ?

दिवाकर मुक्तिबोध

छत्तीसगढ़ के आगामी विधान सभा चुनाव में क्या कांग्रेस भाजपा को सत्ता से बेदखल कर सकती है? चूंकि वतर्मान कायर्काल पूर्ण होने के लिए करीब ढाई वर्ष शेष है इसलिए अभी यह सवाल अप्रासंगिक है फिर भी पार्टी की जमीनी स्तर पर चल रही तैयारियों को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि वह भाजपा को माकूल जवाब देने की स्थिति में है और यदि मुद्दों पर आधारित उसकी आक्रामकता और जनता से जुड़ाव सघन हुआ तो कोई कारण नजर नहीं आता कि वह चुनाव न जीत सके। यह इसलिए भी संभव है क्योंकि विष्णुदेव साय सरकार का अब तक का कामकाज सामान्य–जन की दृष्टि से भी अप्रभावी है। उसकी विपरीत छवि 2028 के चुनाव में उसकी संभावनाओं को कमजोर कर रही है। यद्यपि भाजपा हमेशा चुनावी मोड में रहती है तथा एक चुनाव के निपटने के बाद अगले के लिए उसकी सांगठनिक गतिविधियां शुरू हो जाती हैं लेकिन किसी भी चुनाव के संदर्भ में सरकार का कामकाज बहुत मायने रखता है।

लिहाजा चुनाव के पूर्व प्रदेश संगठन व सरकार के स्तर पर भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व कुछ इसी तरह फेरबदल कर सकता है ताकि मुख्य मंत्री विष्णुदेव साय के हाथ मजबूत हो सके। उन्हें हटाने की संभावना नजर नहीं आती। वजह स्पष्ट है। एक तो वे स्वच्छ सरल प्रकृति के हैं दूसरे वे उस आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करते है जो चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाता है। पिछले चुनाव में इसी समाज की 29 में से 18 सीटें भाजपा ने जीती थीं। इसलिए उन्हें हटाने का जोखिम पार्टी नहीं उठा सकती। इसी संदर्भ में एक और वजह है – बस्तर व उसका विकास। बस्तर के नक्सल मुक्त होने के बाद उसके कथित विकास का संकल्प सरकार की उच्च प्राथमिकता में है जिसे अडानी जैसे उद्योगपतियों के जरिए पूरा करने का संकल्प लिया गया है। इसके अलावा चुनाव की दृष्टि से भी एक और प्रमुख कारण है कांग्रेस की गतिशीलता, उसकी आक्रामकता जो अब भाजपा सरकार व संगठन के लिए चिंता का विषय है। इसीलिए साय सरकार को उसकी कमजोर छवि से बाहर निकालने मंत्रिमंडल में फेरबदल अवश्यंभावी प्रतीत होता है। राजनीतिक गलियारे में इसकी चर्चा काफी समय से चल रही है।

2028 के चुनाव के लिए भाजपा जहां अपनी विशिष्ट तैयारियों में लग चुकी है वही दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है। दरअसल प्रदेश कांग्रेस अब उस राह पर चलती दिखाई दे रही है जो उबड–खाबड नहीं सीधा–सपाट है और पार्टी को सीधे चुनाव मैदान में ले जाता है। वह अपने अंतर्विरोधों से उबरने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के तीन बड़े नेता भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव व चरणदास महंत गुटीय प्रतिद्वंदिता को फिलहाल किनारे रखकर जनहित के अनेक मुद्दों पर अलग–अलग व संयुक्त रूप से सड़क पर उतरे हैं। संगठन को नये जिलाध्यक्ष मिल गए हैं जो अपेक्षाकृत युवा हैं। अनुभव व युवा ऊर्जा दोनों का संयुक्त मेल इस नयी कांग्रेस में दिखाई पड़ता है जिसे राहुल गांधी की कांग्रेस कहा जाता है। राजनीति से परे लेकिन कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ाव महसूस करने वाले लोगों के दिलों में उम्मीदें जग रही है कि संगठन कुछ बेहतरी की ओर बढ़ रहा है। अपनी कमजोरियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है। इस संदर्भ में कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर को अहम माना जा रहा है। अभनपुर में हाल ही सम्पन्न जिलाध्यक्षों व प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों के दस दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के दौरान राहुल गांधी, केसी वेणुगोपाल, अलका लांबा, सचिन पायलट, पवन खेड़ा, भूपेश बघेल, चरणदास महंत , टीएस सिंहदेव, दीपक बैज सहित अन्य वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन से प्रतीत होता है कि प्रदेश कांग्रेस उन गलतियों को दुहराना नहीं चाहती जिनकी वजह से उसे 2023 में तथा इसके पूर्व के चुनावों में सत्ता से बेदखल होना पड़ा था। इस मायने में अभनपुर शिविर कांग्रेस व उसके नये जिलाध्यक्षों के लिए उत्साहवर्धक रहा है।

यह स्पष्ट है कि चुनाव जीतने के दो ही मंत्र है – जनता से सीधा संवाद तथा संगठन में एकजुटता जो भीतर व बाहर से दिखाई देनी चाहिए। शिविर के दौरान युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया। उन्हें तयशुदा गांवों में एक रात बिताने तथा मनरेगा श्रमिकों के बीच काम करने भेजा गया ताकि वे जमीनी हकीकत से वाकिफ हो सके। प्रशिक्षण शिविर में मीडिया सहित चुनाव प्रबंधन के तमाम पक्षों विशेषकर बूथ मैनेजमेंट पर विस्तार से बातें हुईं तथा विचार साझा किए गए।

शिविर के दस दिन पूरे हो गए हैं। अब प्रशिक्षित जिलाध्यक्षों को अपने–अपने जिलों में सक्रिय होना है। कांग्रेस का युवाओं पर ज्यादा जोर है। यद्यपि वरिष्ठ एवं उम्रदराज नेताओं के अपने–अपने गुट अभी भी काफी प्रभावशाली हैं लेकिन नये युवा नेताओं के साथ उनका तालमेल बिठाने की कवायद चल रही है। वैसे यह स्थापित सत्य है कि कांग्रेस यदि खुद को बदलने के तैयार है तो उसका फार्मूला एक ही है – परस्पर विश्वास और अपने राजनीतिक स्वार्थ को परे रखकर पार्टी के प्रति सम्पूर्ण निष्ठा की भावना। यदि ऐसा हो सका तो दूसरा मंत्र है– आम लोगों की तरह आम बने रहना , उनके बीच घुल–मिल जाना, उनका भरोसा जीतना, शहरों व गांवों की जमीनी हकीकत को समझना तथा उनसे निरंतर संवाद बनाए रखना। राज्य की सत्ता गांवों से ही निकलती है। इसलिए आपसी संवाद व विचार विमर्श की निरंतरता के लिए सिर्फ एक शिविर काफी नहीं है। जिलों में समय–समय पर कार्यकर्ताओं के लिए भी ऐसे शिविर आयोजित होने चाहिए। इससे ऊर्जा मिलती है, उत्साह बढ़ता है। जाहिर है कि शिविर से युवाओं को मार्गदर्शन तो मिल सकता है पर उसे व्यवहार में उतारने के लिए कठिन श्रम व इमानदार कोशिशों की आवश्यकता है। क्या नये जिलाध्यक्ष यह कर पाएंगे? यह भी सवाल है कि क्या सुविधाभोगी व गुटीय राजनीति में उलझे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अपने युवाओं के पीछे खड़े रहेंगे ?

संगठन के नेताओं को यह समझना होगा कि कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने, उनका विश्वास जीतने तथा उन्हें सम्मान देने के अलावा जीत का कोई और रास्ता नहीं है। यदि अगले दो–ढाई वर्षों में प्रदेश कांग्रेस संगठन ने यह काम कर दिया तो जो चुनावी फौज तैयार होगी वह निश्चित रूप से भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने में समर्थ होगी। फिलहाल कांग्रेस में यह ज़िद नजर आ रही है। अब यह देखना होगा कि यह ज़िद आने वाले महीनों में संगठन की कायर्शैली और चुनावी तैयारियों में कितनी दिखाई देती है।

डिप्रेशन से छुटकारा दिला सकता है चीकू

आलू की तरह दिखने वाला फल चीकू सपोटा के नाम से भी जाना जाता है। चीकू में विटामिन-बी, विटामिन ई, पोटैशियम,फाइबर और मिनरल आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। जो शरीर को कई बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। चीकू खाने से त्वचा, दिमाग और पाचन अच्छा रहता है। चीकू खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा मिलती है। चीकू का हर भाग स्वास्थ्य लाभों से भरा है इसके पत्ते, जड़ और छाल को औषधी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में आइए जानते हैं चीकू खाने से व्यक्ति को मिलते हैं कौन से गजब के फायदे।

हड्डियां बनाए रखे मजबूत

चीकू में कैल्शियम, आयरन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो शरीर की हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। चीकू का रोजाना सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने का काम करता है। चीकू खाने से बुढ़ापे की वजह से होने वाली कमजोर हड्डियों को ठीक करने में भी मदद मिलती है।

एनर्जी

चीकू को एनर्जी का अच्छा सोर्स माना जाता है। इसमें मौजूद कार्बोहाइड्रेट शरीर को एनर्जी देने का काम करते हैं। जिन लोगों को एनर्जी की कमी महसूस होती है उनके लिए चीकू का सेवन फायदेमंद हो सकता है।

वेट लॉस

चीकू शरीर के मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, जिसकी वजह से व्यक्ति को लंबे समय तक भूख का अहसास नहीं होता और वेट लॉस में मिलती है। चीकू को दिन में किसी भी समय खाया जा सकता है। ये शरीर को तुरंत एनर्जी देने के साथ शरीर को मजबूत भी बनाता है।

डिप्रेशन में राहत

चीकू दिमाग को सेहतमंद बनाए रखने के साथ नींद न आने की समस्या को भी दूर करता है। चीकू का सेवन करने से गहरी और अच्छी नींद आती है। चीकू में मौजूद तत्व दिमाग में ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करते हैं। इतना ही नहीं चीकू का सेवन डिप्रेशन को दूर करने के लिए भी किया जा सकता है।

इन टिप्स से रखें मेंटल हेल्थ का ख्याल

आजकल तनाव न चाहते हुए भी हम सभी की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। स्ट्रेस का बुरा असर, हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ पर होता है। अक्सर फिजिकल हेल्थ खराब होने पर जब इसके लक्षण नजर आते हैं, तो हम आसानी से इन्हें समझ लेते हैं और इसे ठीक करने की कोशिश में भी लग जाते हैं। लेकिन, मेंटल हेल्थ खराब होने पर इसके लक्षणों को हम या तो समझ नहीं पाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। खासकर महिलाएं अपनी मेंटल हेल्थ पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाती हैं। तनाव और चिंता की वजह से अगर आपके चेहरे की मुस्कुराहट भी कहीं खो गई है, तो आपको अपनी मेंटल हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है।

मेंटल हेल्थ का ख्याल रखने के लिए फॉलो करें ये टिप्स

- एक्सपर्ट का कहना है कि मेंटल हेल्थ को सही रखने के लिए, डाइट बहुत जरूरी है। डाइट में पोषक तत्वों की कमी भी मेंटल हेल्थ पर असर डाल सकती है।
- अगर आप अधिक तनाव में हैं और इसकी वजह से आपका किसी काम में मन नहीं लग रहा है या आप हर वक्त परेशान रहती हैं, तो किसी से इस बारे में खुलकर बात जरूर करें।
- ओवरथिंकिंग की वजह से भी मेंटल हेल्थ खराब होती है। इसलिए, किसी भी चीज या डर को लेकर, बहुत अधिक न सोचें वरना इसका असर आपकी सेहत पर हो सकता है।
- किसी बात को बार-बार सोचने से, स्ट्रेस और एंग्जायटी बढ़ने लगती है। इसकी वजह से सिरदर्द, शरीर में दर्द और घबराहट हो सकती है। इसलिए, ज्यादा न सोचें और मन को शांत रखने की कोशिश करें।
- एक्सरसाइज, मेडिटेशन और प्राणायाम भी मेंटल हेल्थ सुधारने में मदद कर सकता है। इसलिए, इसे रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं।
- जब आपको स्ट्रेस या एंग्जायटी महसूस हो, तो गहरी सांस लें और कुछ देर के लिए सारी चीजों पर से ध्यान हटाने की कोशिश करें।
- दिन में कुछ समय उन चीजों को जरूर दें, जो आपको खुशी देती हों।

पैरों के तलवे में होती है जलन इन टिप्स से मिलेगा आराम

क्या आपको भी पैरों के तलवे में जलन होती है, जलन के मारे काम करना भी मुश्किल हो जाता है तो हम आपको कुछ आजमाए हुए टिप्स बता रहे हैं जिससे आपको काफी आराम मिल सकता है। अक्सर लोगों को पैरों के तलवे में जलन की शिकायत होती है। यह एक असहज और परेशान करने वाली समस्या होती है, कई बार जलन के कारण नींद भी नहीं आती है और काम भी प्रभावित होता है। अगर आप भी इस स्थिति का सामना करते हैं तो हम आपको कुछ ऐसे उपाय बता रहे हैं जिससे आपको तलवे में जलन से राहत मिल सकती है।

पैरों के तलवे में जलन क्यों होती है?

- पैरों की अत्यधिक गर्मी के कारण ऐसा हो सकता है। अगर आप लंबे वक्त तक जूते पहने रह सकते हैं तो इसके कारण तलवे में जलन हो सकती है।
- खराब रक्त प्रवाह के कारण भी पैरों के तलवे में जलन हो सकती है।
- शरीर में आयरन और विटामिन B12 की कमी के कारण भी यह समस्या हो सकती है।

पैरों के तलवे की जलन दूर करने के उपाय

- तलवे में अगर बहुत ज्यादा जलन होती है तो आप ठंडा पानी में 20 मिनट तक पैरों को डूबा कर रख सकते हैं। आप चाहे तो इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े डाल सकते हैं, इससे काफी आराम महसूस होगा।
- इसके अलावा आप तलवे में हो रही जलन को दूर करने के लिए तलवों की मालिश कर सकते हैं, मालिश करने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जलन में आराम मिलता है।
- अपने आहार में आयरन विटामिन B12 जैसे पोषक तत्व शामिल करें, इससे शरीर में खून बढ़ता है और रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है।
- तलवे के जलन को कम करने के लिए आप मेहंदी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रात के समय पैरों में मेहंदी लगा लें और सुबह उठकर धो लें इससे तलवे में ठंडक मिलती है।
- इसके अलावा आप पैरों में एलोवेरा और चंदन का लेप लगा सकते हैं। इन दोनों ही चीजों की तासीर ठंडी होती है। इसका पेस्ट बना ले और तलवे पर भी 20 मिनट तक लगा कर रखें, फिर साफ पानी से धो लें।
- अगर इन उपायों को आजमाने के बाद भी आपको राहत नहीं मिलती है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।

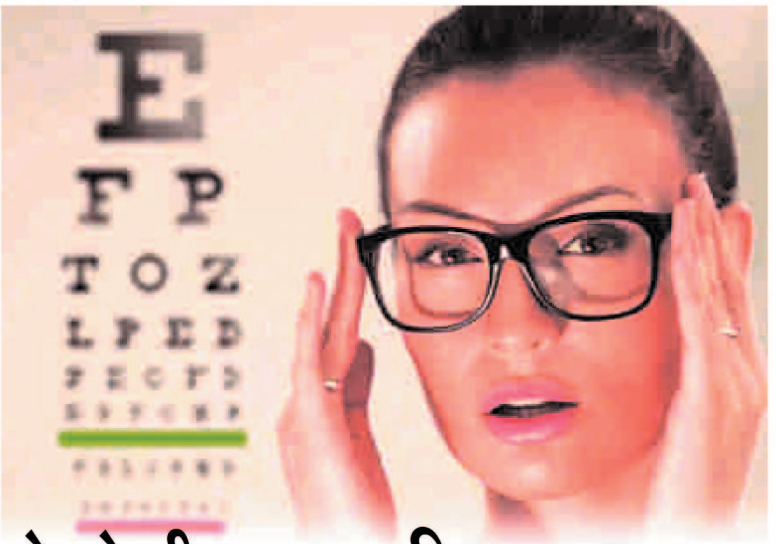

देखने की क्षमता प्रभावित करता है प्रेसबायोबिया विकार

प्रेसबायोबिया आंखों से जुड़ी एक बीमारी जिसमें आंखों की करीब वस्तुओं पर फोकस करने की क्षमता कम हो जाती है।

प्रेसबायोपिया आंखों से संबंधित एक विकार है। इस शब्द को ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है बूढ़ी आंख, यह एक ऐसी स्थिति होती है जब आपकी धीरे-धीरे चीजों को करीब से स्पष्ट रूप से देखने की क्षमता खो देती है। इस स्थिति में नजदीकी वस्तुओं पर तेजी से ध्यान केंद्रित करने की क्षमता धीरे-धीरे खत्म हो जाती है। आमतौर पर यह 40 से 45 साल की उम्र में शुरू होती है और समय के साथ बिगड़ती जाती है। यह बाकी उम्र से संबंधित दृष्टि समस्याओं जैसे अंधापन, हाइपरोपिया मायोपिया से अलग है। यह एक प्राकृतिक परिवर्तन है जो लगभग सभी लोगों को प्रभावित करता है। इसको लेकर हमने हेल्थ एक्सपर्ट से बाती है।

प्रेसबायोपिया के लक्षण

- छोटी लेखन सामग्री पढ़ने में कठिनाई होती है, खासकर अगर रोशनी बहुत कम है।
- जब आपको यह बीमारी होती है तो आप अपने स्मार्टफोन या किसी भी किताब, मेनू , लेबल को अधिक स्पष्ट रूप से देखने के लिए अपनी आंखों से दूर रखते हैं।
- कोई नजदीकी काम करते हैं या कुछ नजदीक रखकर पढ़ते हैं तो इसे सिर में दर्द और आंखों में तनाव होना।

प्रेसबायोपिया के कारण

- आंखों की उम्र बढ़ाने की प्रक्रिया प्रेसबायोपिया की ओर ले जाती है।
- समय के साथ आंखों का आंतरिक लेंस लचीला नहीं रहता है, जिससे नजदीकी वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करना मुश्किल हो जाता है।
- उम्र के साथ लेंस को नियंत्रित करने वाली मांसपेशियां कमजोर हो जाती है।
- यह अनुवांशिक भी हो सकती है। अगर आपके घर में माता-पिता या दादा- दादी कोप्रेसबायोपिया था तो आपको भी यह स्थिति होने की संभावना ज्यादा रहती है।
- डायबिटीज,उच्च रक्तचाप और दिल की बीमारी सहित कई स्वास्थ्य स्थितियों में भीप्रेसबायोपिया हो सकता है।
- आंखों की चोट के कारण भी लेंस को नियंत्रित करने वाले मांसपेशियों को नुकसान पहुंच सकता है,इससे भी प्रेसबायोपिया हो सकता है।

डाइट से एडेड शुगर हटाना फायदेमंद!

चीनी...यह एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मुंह में मिठास घुलने लगती है। चीनी जिस तरह से हर मिठाई, हलवे और खीर का स्वाद बढ़ाती है, उसी तरह से बीमारियों का खतरा भी बढ़ाती है। वजन बढ़ने से लेकर डायबिटीज तक, चीनी शरीर के लिए कई तरह से नुकसानदायक मानी जाती है। ऐसे में कई लोगों ने चीनी को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा दिया है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चीनी को अपनी थाली से बिल्कुल नहीं निकाल पा रहे हैं और भरपूर मीठा खा रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक दिन में कितना चीनी यानी शुगर का सेवन करना आपके लिए सेफ है।

अति किसी भी चीज की बुरी होती है, यह बात चीनी के सेवन के मामले में भी लागू होती है। डॉक्टर्स से लेकर हेल्थ एक्सपर्ट भी इस बात को मानते हैं कि व्हाइट शुगर सेहत के लिए कई तरह से हानिकारक होती है। अब इस बात पर इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी मुहर लगा दी है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशियन ने कुछ समय पहले भारतीयों की डाइट को लेकर 17 गाइडलाइन्स की एक ज्वाइंट रिपोर्ट जारी की थी। जिसमें से एक गाइडलाइन में भारतीयों को एक दिन में कितनी शुगर लेनी चाहिए, इसका जिक्र किया गया है।

एक दिन में कितनी चीनी का सेवन करना चाहिए?

अगर एक सामान्य एडल्ट प्रति दिन 2000 कैलोरी लेता है और इसका 5 परसेंट यानी 25 ग्राम शुगर इन्टेक करता है तो वह हाई शुगर कहलाता है। अगर इसे सामान्य भाषा में समझें 20-25 ग्राम शुगर का एक दिन में सेवन किया जा सकता है।

संभव रहे तो चीनी को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा देना चाहिए। क्योंकि इसमें कैलोरी के अलावा किसी भी तरह के न्यूट्रिशियन शामिल नहीं होते हैं। कैलोरी शरीर के लिए तभी फायदेमंद होती है जब विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर के साथ ली जाए।

रिपोर्ट के मुताबिक, एडेड शुगर को अपनी डाइट से पूरी तरह से हटा देना फायदेमंद होता है। एडेड शुगर में चीनी, गुड़, ग्लूकोज, फरूक्टोज, डेक्सट्रोज, शुगर सिरप आदि चीजें आती हैं। किसी भी चीज में शुगर को मिलाकर खाना सेहत के लिए किसी भी तरह से बेहतर नहीं होता है क्योंकि इससे शरीर में सिर्फ कैलोरी बढ़ती है।

चीनी के बहुत सारे नुकसान होते हैं।

क्या नेचुरल शुगर है सेफ?

रिपोर्ट में फलों और दूध में पाई जाने वाली शुगर को नेचुरल बताया है। फलों और खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद रहने वाली शुगर को एक्सपर्ट भी सेफ मानते हैं. लेकिन सभी फलों और खाने की चीजों में मौजूद शुगर आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं होती है। मेडिकल बॉडी ने अपनी रिपोर्ट में गन्ने के जूस को सेहत के लिए हानिकारक माना है। गन्ने के जूस में शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और यह आपको बीमार कर सकती है। 100 द्रव के गन्ने के जूस में 15 ग्राम शुगर होती है, ऐसे में इसका अधिक सेवन आपकी सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है। शरीर में अत्यधिक शुगर से कई बीमारियों को न्योता मिल सकता है।

रिपोर्ट में सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन पर भी ऐतराज जताया गया है. मेडिकल बॉडी का मानना है कि सॉफ्ट ड्रिंक्स में सिर्फ हाई शुगर कंटेंट होता और न्यूट्रिशियनल वैल्यू ना के बराबर होती हैं। ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक्स के सेवन से मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, दांतों की समस्या और दिल की बीमारी भी हो सकती है। साथ ही सॉफ्ट ड्रिंक्स पानी और फ्रेश फ्रूट्स की जगह नहीं ले सकते हैं, ऐसे में उन्हें जितना हो सके इनका सेवन करने से बचना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक्स की जगह छाछ, नींबू पानी, बिना चीनी वाले फ्रूट जूस और नारियल पानी के सेवन की सलाह दी गई है। जूस से ज्यादा फलों के सेवन पर भी जोर दिया है। रिपोर्ट में ऐसा कहा गया है कि फ्रूट फाइबर और न्यूट्रियंट वैल्यू की वजह से ज्यादा सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं।

गाइडलाइन्स में भारतीयों की हेल्दी डाइट पर जोर दिया गया है। रिपोर्ट में हरी सब्जियों के अत्याधिक सेवन की बात की गई है और डाइट से प्रोसेस्ड फूड, पैक्ड जूस, सॉफ्ट ड्रिंक को हटाने की सलाह दी गई है। साथ ही चाय और कॉफी के सेवन को भी कम करने की बात की गई है, क्योंकि इसमें कैफीन होता है जो सेहत के लिए हानिकारक साबित साबित हो सकता है।

शरवरी-वेदांग रैना की तुलना पर इम्तियाज अली ने तोड़ी चुप्पी

फिल्ममेकर इम्तियाज अली इन दिनों अपनी नई फिल्म 'मैं वापस आऊंगा' को लेकर खूब चर्चा में हैं। इस फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, खासकर इसके इमोशनल और दिल को छू लेने वाले कहानी के लिए।

एक्टिंग बॉक्सिंग की तरह नहीं होती

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में इम्तियाज अली ने फिल्म के दो यंग स्टार्स शरवरी और वेदांग रैना को लेकर चल रही तुलना पर अपनी बात रखी। उन्होंने बहुत ही सादे और समझदारी भरे अंदाज में कहा कि एक्टिंग कोई मुकाबला नहीं है। उन्होंने कहा, 'एक्टिंग बॉक्सिंग की तरह नहीं होती। कलाकार एक-दूसरे के खिलाफ नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करते हैं। कुछ लोगों को वेदांग ज्यादा पसंद आए, तो कुछ को शरवरी, और ये बिल्कुल ठीक है।'

क्या है फिल्म की कहानी

फिल्म की कहानी 1947 के भारत-पाकिस्तान विभाजन के समय पर आधारित है, जिसमें प्यार, जुदाई और हीलिंग की इमोशनल कहानी दिखाई गई है। फिल्म में नसीरुद्दीन शाह का किरदार काफी मजबूत है, लेकिन इसके साथ ही शरवरी और वेदांग की लव स्टोरी भी लोगों का दिल जीत रही है।

दोनों ने एक टीम की तरह काम किया है

इम्तियाज अली ने दोनों की केमिस्ट्री की भी खूब तारीफ की। उन्होंने कहा, 'जब शरवरी और वेदांग साथ में स्क्रीन पर आते हैं, तो सीन और भी खूबसूरत बन जाते हैं। मेरे करियर में मैंने इतनी शानदार को-एक्टर्स की जोड़ी बहुत कम देखी है। दोनों ने एक टीम की तरह काम किया है।'

अपने हॉलीवुड करियर को बॉलीवुड के मुकाबले कमतर आंकती हैं प्रियंका

एक्टर प्रियंका चोपड़ा उन चुनिंदा भारतीय एक्टर्स में से एक हैं जिन्होंने बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों जगह कामयाबी हासिल की है। अपने हिंदी फिल्मी करियर के पीक पर वह इंटरनेशनल मौकों की तलाश में अमेरिका चली गईं। हालांकि, कई ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में काम करने के बावजूद प्रियंका को लगता है कि हॉलीवुड में उनका काम भारतीय सिनेमा में किए गए उनके काम के मुकाबले कम ही है।

हॉलीवुड में अभी बेस्ट काम आना बाकी

कान लायंस सम्मेलन में बोलते हुए प्रियंका ने हॉलीवुड में अपने करियर पर नजर डाली और अलग-अलग प्रोजेक्ट्स के साथ इसे और आगे बढ़ाने की इच्छा व्यक्त की। 'बेवॉच', 'द मैट्रिक्स रेजरेक्शन्स' और हाल ही में रिलीज हुई 'द ब्लफ' जैसी हॉलीवुड फिल्मों में शानदार अभिनय के बावजूद प्रियंका ने कहा कि उन्हें लगता है कि हॉलीवुड में उनका बेस्ट काम अभी आना बाकी है। एक्ट्रेस ने कहा कि अपने हिंदी भाषा के करियर में मैंने सभी बेहतरीन फिल्म निर्माताओं और अभिनेताओं के साथ काम किया है, मैंने अद्भुत कहानियां सुनाई हैं और अलग-अलग जॉनर में काम किया है। जबकि अमेरिका में हॉलीवुड में अपने अंग्रेजी भाषा के काम में मैंने ऐसा उतना नहीं किया है।

शादी और मां बनने के बाद बदल जाती हैं प्राथमिकताएं

प्रियंका ने कहा कि अब उनका अगला चरण इस बात पर केंद्रित होगा कि वो हॉलीवुड में भी बॉलीवुड की तरह अलग-अलग तरह की भूमिकाएं निभाएं। अगला बदलाव यह पता लगाने के बारे में है कि मैं अपने हॉलीवुड के काम में अपने किरदारों में वैसी ही विविधता कैसे ला सकती हूं जैसी भारत में ला पाई हूं। इस दौरान प्रियंका ने शादी और मां बनने के बाद अपनी जिंदगी के बारे में भी खुलकर बात की और माना कि उनकी जिंदगी बहुत ज्यादा बदल गई है। उन्होंने कहा कि आपकी प्राथमिकताएं सच में बदल जाती हैं। अब मैं बस अपना सामान पैक करके किसी फिल्म के लिए नहीं निकल जाती। मैं साल में पांच फिल्में नहीं करती। मैं पहले की तरह यात्रा नहीं करती। मैं इस बात को लेकर बहुत ज्यादा सोच-समझकर फैसला करती हूं कि मैं अपना समय कैसे और किसके साथ बिताती हूं। मैं एक कामकाजी मां के तौर पर जिंदगी को संभाल रही हूं। अब मुझे अपनी मां के लिए और भी ज्यादा सम्मान महसूस होता है।

सितंबर 2026 तक पूरी होगी 'राका' की शूटिंग

'एए23' पर काम शुरू करेंगे 'पुष्पा' एक्टर अल्लू अर्जुन

'पुष्पा' फ्रैंचाइजी से पूरे भारत में मशहूर होने के बाद, अल्लू अर्जुन अपने करियर के अगले पड़ाव के लिए तैयार हो रहे हैं। पिछले दो वर्षों से अपनी फिल्मों की कामयाबी और ऑफ-स्क्रीन विवादों की वजह से चर्चा में रहे यह एक्टर अब अपने करियर के दो सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स - 'राका' और 'एए23' के लिए तैयारी कर रहे हैं।

'राका' पर ध्यान दे रहे अल्लू अर्जुन

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल्लू अर्जुन अभी 'राका' के लिए अपने हिस्से की शूटिंग पूरी करने पर ध्यान दे रहे हैं। इस फिल्म का प्रोडक्शन 2026 के आखिर तक चलने की उम्मीद है। खबर है कि एक्टर सितंबर 2026 तक अपना शेड्यूल पूरा करना चाहते हैं। इसके बाद वह अपना ध्यान फिल्म 'एए23' पर देना चाहते हैं। इसकी शूटिंग दिसंबर में शुरू होने की संभावना है।

बड़े प्रोडक्शन की होगी जरूरत

कहा जा रहा है कि फिल्म 'राका' बड़े पैमाने पर बनाई जा रही है। इसमें बहुत ज्यादा विजुअल इफेक्ट्स और बड़े प्रोडक्शन की जरूरत होगी। बताया यह भी जा रहा है कि फिल्मिंग पूरी होने के बाद भी वीएफएक्स के ज्यादा इस्तेमाल की वजह से फिल्म को लंबे पोस्ट-प्रोडक्शन प्रोसेस से गुजरना होगा। खबर है कि मेकर्स इसे 2028 के बीच में रिलीज करने की सोच रहे हैं, जिससे उन्हें तकनीकी पहलुओं को बेहतर बनाने और विजुअल को अच्छा करने के लिए काफी समय मिल जाए।

'एए23' को लेकर बढ़ी उत्सुकता

अल्लू अर्जुन 'एए23' पर काम करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस फिल्म के ऐलान के बाद से ही लोगों में इसे लेकर काफी उत्सुकता है और इसे एटली डायरेक्ट कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इस फिल्म को ग्लोबल लेवल पर एक कमर्शियल एंटरटेनर के तौर पर प्लान किया जा रहा है, जिसमें भारत के सबसे बड़े स्टार्स में से एक और सबसे सफल मास फिल्ममेकर्स में से एक साथ आ रहे हैं।

फिल्मों के चुनाव को लेकर चेतना पांडे का बेबाक बयान

अभिनेत्री चेतना पांडे को हालिया रिलीज फिल्म 'हॉन्टेड उडीः इकोज ऑफ द पास्ट' से दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। इस सफलता के बीच चेतना ने करियर, फिल्मों के चुनाव और भविष्य की योजनाओं को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि अब वह केवल ऐसे प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहती हैं, जो उन्हें एक कलाकार के तौर पर आगे बढ़ाएं और दर्शकों के दिलों पर गहरी छाप छोड़ें।

चेतना पांडे ने कहा, ''करियर के इस पड़ाव पर मैं खुद को किसी एक तरह के किरदार या फिल्म शैली तक सीमित नहीं रखना चाहती। हॉरर फिल्म में काम करने के बाद मुझे इस शैली की ताकत का एहसास हुआ है, इसलिए मैं आगे भी हॉरर फिल्मों में काम करना चाहूंगी। मैं सिर्फ इसी शैली तक सीमित नहीं रहना चाहती। एक कलाकार के रूप में मेरा सबसे बड़ा सपना खुद को और अपने दर्शकों को लगातार नए रूप में चौंकाना है।''

अभिनेत्री ने कहा, ''मैं ऐसा किरदार निभाना चाहती हूं, जो मुझे भावनात्मक, मानसिक और शारीरिक रूप से चुनौती दे और मुझे आगे बढ़ाता रहे। चाहे कोई बड़ी कमर्शियल फिल्म हो, थ्रिलर हो या फिर बायोपिक, मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने यह बात रखती है कि मेरा किरदार दर्शकों के मन में लंबे समय तक बना रहे।'

चेतना ने कहा, ''मुझे फिल्म में ज्यादा स्क्रीन टाइम नहीं चाहिए। मैं ऐसे रोल्स को प्राथमिकता देती हूं, जिनकी कहानी में दम हो और जो कुछ कहने की ताकत रखते हों। मैं कैवल ग्लैमर दिखाने वाली भूमिकाओं की बजाय ऐसी कहानियों का हिस्सा बनना चाहती हूं, जो लोगों को सोचने पर मजबूर करें। हर नया प्रोजेक्ट मुझे पहले किए गए काम से आगे ले जाए और कुछ नया सिखाए।''

चेतना ने कहा, ''मैं अभी भी इस पूरे अनुभव को समझने और महसूस करने की कोशिश कर रही हूं। जब कोई कलाकार लंबे समय तक किसी फिल्म पर मेहनत करता है, कई तरह की चुनौतियों का सामना करता है और यह उम्मीद करता है कि दर्शक उसके काम को पसंद करेंगे, तब सफलता मिलने के बाद उस पल को तुरंत समझ पाना आसान नहीं होता।'' ''हॉन्टेड 3डी' फिल्म की सफलता पर खुशी जताते हुए चेतना ने कहा, 'पिछले कुछ दिन जश्न से ज्यादा आभार के रहे हैं। मैंने सबसे पहले परिवार, दोस्तों और उन लोगों से बात की, जिन्होंने इस सफर में हर कदम पर मेरा साथ दिया। मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी यही है कि मेरे करीबी लोग मेरी सफलता से खुश हैं।'

बदलते दौर के साथ कॉमेडी बदली है, हमसे ज्यादा प्रेशर में फिल्म एक्टर्स हैं

अली असगर उन सधे हुए कलाकारों में से है, जिन्होंने हर किरदार में जान डाली है। बात कॉमेडी की आई, तो उन्होंने ऐसी छाप छोड़ी है, जो ताउम्र दुनिया को हंसाते रहेगी। टीवी पर 'कॉमेडी सर्कस', 'जरा नचके दिखा', 'एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा' जैसे शोज के जरिए वह दशकों से दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं।

55 साल के अली कहते हैं कि बदलते दौर के साथ अब कॉमेडी भी बदल गई है। खास बातचीत में उन्होंने कॉमेडी के बदलते स्वरूप पर दो टूक राय दी। कहा, 'जैसे-जैसे दौर बदलता है, वैसे-वैसे कॉमेडी भी बदलती है। जब 'कॉमेडी सर्कस' शुरू हुआ तो बहुत लंबा चला। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वही चीज आज उतना चल पाएगी, क्योंकि आखिर आप कितनी चीजें क्रिएट करोगे।'

मुंबई में पैदा हुए अली असगर मानते हैं कि समय के साथ ही ऑडियंस भी जल्दी ऊब जाती है। अब दर्शकों का अटेंशन स्पैन कम हो गया है। अब इंस्टाग्राम रील्स वगैरह के कारण 15-30 सेकंड तक या ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट तक ही आप दर्शकों को रोक सकते हैं। इसके बाद सारा दारोमदार आपके कंटेंट पर है। यदि कंटेंट में दम नहीं है, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप ऑडियंस को खो देंगे। जहां तक क्लीन कॉमेडी की बात है, तो दादा-दादी से लेकर बच्चों तक, पूरा परिवार एकसाथ देख सके, वह कंटेंट तो और भी मुश्किल है।

हमसे ज्यादा प्रेशर फिल्मी कलाकारों पर है

बदलते वक्त में फिल्म इंडस्ट्री के लोगों पर भी प्रेशर बढ़ा है। कई सितारे इस बारे में अपनी बात कह भी चुके हैं। अली कहते हैं, 'प्रेशर तो हर जगह है, हर फील्ड में है। सिनेमा एक्टर्स को सबसे ज्यादा प्रेशर होता है कि शुक्रवार को क्या होगा। उनके सिर पर तो करोड़ों रुपये का दांव लगा होता है। टीवी में हम एक्टर्स का इतना कुछ दांव पर नहीं होता, क्योंकि पैसा, प्रोडक्शन किसी और का है। हम तो किरदार निभाते हैं। जो कैरेक्टर हमें मिलता है, हम उसे अच्छे से निभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर वह चीज नहीं चलती है, तो उसका दोष भी हमारे ऊपर आ जाता है। कई बार फिल्म नहीं चलती है तो डायरेक्टर को कोई दोष नहीं देता है, बल्कि लोग कहते हैं कि उस कलाकार की फिल्म नहीं चली। लेकिन सच तो यह है कि यह पूरी एक टीम है, कई डिपार्टमेंट उसमें जुड़े होते हैं।'

हर कलाकार के लिए थिएटर जरूरी

अली असगर उन कलाकारों में से हैं, जो टीवी और फिल्मों के साथ ही थिएटर के मंच पर भी लगातार परफॉर्म करते हैं। हाल ही वह दिल्ली में भी रंगमंच पर 'टॉम एंड जैरी' नाम के नाटक की प्रस्तुति करते देखे गए। जब अली असगर से पूछा गया कि टीवी के दर्शक और थिएटर के दर्शकों में क्या अंतर होता है? उन्होंने जवाब दिया, 'जिस शिद्दत से हम थिएटर में परफॉर्म करते हैं, उसी शिद्दत से हमें दर्शकों की प्रतिक्रिया भी मिलती है। यहां आपको तुरंत रिस्पॉन्स मिलता है। जैसे ही प्ले शुरू होता है, आपको ऑडियंस के साथ तुरंत रिश्ता बनाना होता है। वह रिश्ता बनाना चुनौतीपूर्ण भी है, आकर्षित भी करता है और जरूरी भी है। वहां आपको बहुत सावधान भी रहना होता है, क्योंकि कोई कट तो होता नहीं है। इसलिए मौके को देखकर ही खुद को सुधारना होता है। मैं तो सभी कलाकारों से कहूंगा कि आप लोग भी आकर थिएटर करें। यह हमारे लिए एक मेंटल एक्सरसाइज है और चैलेंजिंग भी है।'

सहकारिता की पहल से खेती को मिली नई उड़ान, ड्रोन से 7 मिनट में हुआ एक एकड़ में उर्वरक छिड़काव

किसान आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हुए सब्जी, फूल और अन्य फसलों की कर रहे हैं खेती

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

सहकारी सप्ताह के तृतीय दिवस पर केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के पाँच वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर बेमेतरा जिले में किसानों को ड्रोन तकनीक के माध्यम से उर्वरक छिड़काव का प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों से जोड़ते हुए खेती को अधिक लाभकारी, सुरक्षित और लागत प्रभावी बनाना रहा।

कार्यक्रम में ड्रोन के जरिए खेतों में उर्वरक छिड़काव का लाइव प्रदर्शन किया गया। विशेषज्ञों ने बताया कि पारंपरिक तरीके की तुलना में ड्रोन से छिड़काव तेज, सटीक और समान रूप से होता है। इससे उर्वरक की बर्बादी कम होती है, श्रम और समय की बचत होती है तथा किसानों की उत्पादन लागत में भी कमी आती है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार ड्रोन तकनीक से फसलों की निगरानी भी अधिक प्रभावी ढंग से की जा सकती है। साथ ही किसानों को रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के सीधे संपर्क से बचाव मिलता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम भी कम होते हैं।

कृषक सदस्य विजय पटेल और कमल पटेल ने बताया कि वे पिछले पाँच वर्षों से आधुनिक कृषि तकनीकों का उपयोग करते हुए सब्जी, फूल एवं अन्य फसलों की खेती कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सहकारिता, कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के सहयोग से अत्याधुनिक कृषि यंत्रों का लाभ मिल रहा है। ड्रोन के माध्यम से मात्र 7 मिनट में एक एकड़ क्षेत्र में उर्वरक का छिड़काव पूरा हो

जाता है, जिससे समय और लागत दोनों में उल्लेखनीय बचत हो रही है। उन्होंने इसे किसानों के लिए बेहद उपयोगी तकनीक बताते हुए कहा कि इससे खेती अधिक लाभदायक बन रही है।

इस अवसर पर सहायक पंजीयक ए. के. सिंह, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक विनय कुमार जेहोआश, महेंद्र कुमार टेकाम, सहकारिता विस्तार अधिकारी संदीप वर्मा, सहकारी निरीक्षक पल्लवी मेश्राम, रूपिका यादव, कृषि विभाग के आरईओ राजेश वर्मा, मार्केटिंग प्रबंधक संजय ठाकुर, समिति प्रबंधक उत्तरा टंडन, विनोद कुमार साहू, हरीश कुमार साहू, ड्रोन ऑपरेटर लोकेश साहू, पूरन निर्मलकर, मंशा साहू, हरीश वर्मा, प्रिंस राजपूत सहित बड़ी संख्या में किसान एवं विभागीय अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। सहकारिता विभाग की यह पहल जिले में आधुनिक एवं तकनीक आधारित खेती को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इससे किसानों को कम लागत में बेहतर उत्पादन प्राप्त करने के साथ-साथ कृषि कार्यों में नई तकनीकों को अपनाने के लिए भी प्रोत्साहन मिल रहा है।

खास खबर

एग्रीस्टेक पोर्टल में शत-प्रतिशत किसानों का पंजीयन सुनिश्चित करें-कलेक्टर गोपाल वर्मा

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कलेक्टर गोपाल वर्मा ने समय-सीमा की साप्ताहिक बैठक में जिले के सभी पात्र किसानों का एग्रीस्टेक में शत-प्रतिशत पंजीयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन किसानों का अब तक पंजीयन नहीं हो पाया है, विशेषकर एक्जेम्प्टेड (छूट प्राप्त) श्रेणी के किसानों का प्राथमिकता के आधार पर पंजीयन कराया जाए। इसमें एफआरए (वन अधिकार पट्टाधारी), वन पट्टाधारी, संस्थागत, शासकीय पट्टाधारी तथा ग्राम नौकर श्रेणी के किसान शामिल हैं। इसके साथ ही अन्य छूटे हुए सभी किसानों का पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित करें।

कलेक्टर श्री वर्मा ने कहा कि पूर्व में एग्रीस्टेक पोर्टल में इन श्रेणियों के किसानों के पंजीयन का विकल्प उपलब्ध नहीं होने के कारण उनका पंजीयन नहीं हो सका था। इस वर्ष पोर्टल में इन श्रेणियों के किसानों के लिए पंजीयन का विकल्प उपलब्ध करा दिया गया है। इसलिए संबंधित अधिकारी ऐसे सभी किसानों का चिन्हांकन कर उनका पंजीयन प्राथमिकता से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्य छूटे हुए सभी किसानों का भी पोर्टल में पंजीयन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जिले में किसान पंजीयन के लिए समिति स्तर पर 10 जुलाई 2026 तक विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं।

उन्होंने विभागीय अधिकारियों से कहा कि वे अपनी आईडी में प्राप्त प्रकरणों की लगातार समीक्षा करें तथा समय-सीमा के भीतर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने सुशासन तिहार के लंबित प्रकरणों की जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि आगामी दो दिनों के भीतर सभी लंबित आवेदनों का प्राथमिकता से निराकरण किया जाए। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत स्वीकृत आवासों के निर्माण कार्यों की ब्लॉकवार समीक्षा भी की। कलेक्टर ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवास निर्माण कार्यों में तेजी लाने तथा स्वीकृत आवासों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पात्र हितग्राहियों को शीघ्र आवास उपलब्ध कराना प्रशासन की प्राथमिकता है। बैठक में एडीएम विनय पोयाम, अपर कलेक्टर नरेन्द्र पैकरा, जिले के सभी एसडीएम, तहसीलदार तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

जिला स्तरीय रोजगार मेला के लिए नियोजकों से मांग पत्र आमंत्रित

कवर्धा। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र द्वारा 22 जुलाई 2026 दिन बुधवार को जिला स्तरीय रोजगार मेला का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है। कबीरधाम जिले के ऐसे निजी प्रतिष्ठान, संस्थाओं (स्कूल, हॉस्पिटल, कम्प्यूटर, बीमा, माईक्रो फायनेंस, सेल्स, फेब्रिकेषन, सिक्योरिटी आदि क्षेत्र) जो अपनी संस्था में रिक्त तकनीकी, नॉन तकनीकी पदों पर भर्ती करना चाहते है, उनसे मांगपत्र, रिक्तियाँ आमंत्रित की गई है। मांगपत्र, रिक्तियाँ इस विभाग की वेबपोर्टल https://erojgar.cg.gov.in से या कार्यालय में संस्था का नाम, पूर्ण पता, मोबाईल नंबर, संस्था का पंजीयन क्रमांक, जी.एस.टी. नंबर, पेन कार्ड नंबर, ईमेल आईडी, संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम, पदनाम, मोबाईल नंबर, पद संख्या, आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, वेतन एवं भत्ता, कार्यक्षेत्र (अन्य जानकारी जो आवश्यक हो) की पूर्ण जानकारी के साथ 10 जुलाई 2026 तक प्रेषित कर सकते है। ताकि रोजगार मेला का आयोजन करते हुए, कार्यालय में पंजीकृत अभ्यर्थियों को सूचित कर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके। अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के दूरभाष क्रमांक 07741-299344 से भी संपर्क कर सकते है।

अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 की गतिविधियों को गति देने हुई बैठक

सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है-कलेक्टर

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

जिले में सहकारिता गतिविधियों को और अधिक सशक्त एवं जनभागीदारी आधारित बनाने के उद्देश्य से कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं की अध्यक्षता में जिला सहकारी विकास समिति की बैठक दिशा सभाकक्ष में आयोजित की गई। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष (कउ-2025) के अंतर्गत जिले में संचालित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत समीक्षा करते हुए उनके प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।

बैठक में कलेक्टर ने कहा कि एक पेड़ माँ के नाम अभियान को सहकारिता आंदोलन से जोड़ते हुए अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित की जाए। उन्होंने निर्देशित किया कि जिले की सभी सहकारी संस्थाएं, समितियां एवं संबंधित विभाग अभियान के अंतर्गत व्यापक स्तर पर पौधरोपण करें तथा लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं नियमित देखरेख की भी प्राथमिकता दें, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ सामाजिक सहभागिता का संदेश भी सशक्त रूप से प्रसारित हो।

बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष-2025 के अवसर पर राज्य स्तर से जारी वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के अनुसार जिले में आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्धारित समय-सीमा में गतिविधियों का सफल आयोजन सुनिश्चित करने तथा अधिकाधिक किसानों, महिलाओं, युवाओं एवं ग्रामीणों की सहभागिता बढ़ाने के निर्देश दिए।

बैठक में जिले की अनाच्छादित एवं अल्पसेवित ग्राम पंचायतों में बहुआयामी मत्स्य सहकारी समितियों तथा बहुआयामी दुग्ध सहकारी समितियों के गठन एवं पंजीयन की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण कर पात्र हितग्राहियों को सहकारिता से जोड़ने, नई समितियों के गठन की प्रक्रिया में तेजी लाने तथा शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए।

कलेक्टर सुश्री प्रतिष्ठा ममगाईं ने कहा कि सहकारिता ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का प्रभावी माध्यम है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों, पशुपालकों एवं मत्स्य पालकों की आय में वृद्धि के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए जा सकते हैं। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए शासन की मंशा के अनुरूप सहकारिता आधारित विकास को गति देने पर जोर दिया। बैठक में समिति के अन्य एजेंडों पर भी विचार-विमर्श किया गया तथा अध्यक्ष की अनुमति से आवश्यक सुझावों एवं प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, सहकारिता विभाग, मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से रोशन हुआ भविष्य, अब बिजली बिल हुआ शून्य

नई दृष्टिबिंदु / कवर्धा

कबीरधाम जिले के ग्राम पंचायत समनापुर के निवासी रोशेलाला पाटिल के लिए बढ़ता बिजली बिल हर महीने चिंता का कारण बनता था। उनके घर का मासिक बिजली बिल लगभग पंद्रह सौ से 2 हजार रुपये तक आता था। लेकिन अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित होने के बाद पिछले छह महीनों से उनका बिजली बिल शून्य आ रहा है।

रोशेलाला पाटिल बताते हैं कि पहले बिजली का सीमित उपयोग करना पड़ता था, लेकिन अब वे पंखा, कूलर, फ्रिज, टीवी और मोटर पंप सहित सभी विद्युत उपकरणों का बिना किसी चिंता के उपयोग कर रहे हैं। उनका घर अब केवल बिजली का उपभोक्ता नहीं, बल्कि बिजली उत्पादन करने वाला घर भी बन गया है। उन्होंने बताया कि 3 किलोवाट क्षमता का सोलर प्लांट लगाने में लगभग 2 लाख रुपये की लागत आई। इसमें केंद्र सरकार से 78 हजार रुपये की सब्सिडी मिली है, जबकि राज्य सरकार से 35 हजार रुपये की अतिरिक्त सहायता भी स्वीकृत हुई है। सरकार की इस सहायता से सोलर प्लांट लगवाना उनके लिए आसान हो गया।

श्री पाटिल का कहना है कि सोलर प्लांट लगने के बाद न केवल बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है, बल्कि वे पर्यावरण संरक्षण में भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। भविष्य में यदि आवश्यकता से अधिक बिजली का उत्पादन होगा, तो नेट मीटरिंग के माध्यम से उसका भी लाभ मिलेगा। साथ ही, 3 किलोवाट ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम में बैटरी की आवश्यकता नहीं होने से रखरखाव का खर्च भी कम रहता है। वे अन्य लोगों से भी इस योजना का लाभ लेने की अपील करते हुए कहते हैं कि यह केवल बिजली बिल बचाने की योजना नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक स्थायी निवेश है। एक बार सोलर प्लांट लगाने के बाद वर्षों तक स्वच्छ ऊर्जा का लाभ मिलता है और परिवार की नियमित बचत भी होती है। रोशेलाला पाटिल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस योजना ने उनके परिवार को आर्थिक राहत देने के साथ आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दिया है।

सहकारी सप्ताह के द्वितीय दिवस पर जिला स्तरीय सहकारी संगोष्ठी का हुआ आयोजन

नई दृष्टिबिंदु / खैरागढ़

सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आयोजित सहकारी सप्ताह के द्वितीय दिवस पर जिला खैरागढ़-छुईखदान-गंडई में जिला सहकारी विकास समिति (डीसीडीसी) की बैठक एवं जिला स्तरीय सहकारी संगोष्ठी का आयोजन जिला पंचायत सभाकक्ष में किया गया। संगोष्ठी का विषय "सदस्यों की आय बढ़ाने में एफपीओ एवं पैक्स की भूमिका" रहा, जिसमें जिले की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारियों एवं पदाधिकारियों ने सहभागिता की।

संगोष्ठी में जनपद पंचायत खैरागढ़ की अध्यक्ष श्रीमती डॉ. राजेश्वरी शैलेन्द्र त्रिपाठी, सहकारिता विभाग के वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक एवं नोडल अधिकारी श्री बी.एल. नेताम, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक राजनांदगांव के नोडल अधिकारी श्री योगेन्द्र शर्मा तथा बैंक परिवेक्षक श्री शीतल देवांगन ने सहकारिता आधारित विकास, एफपीओ एवं पैक्स की उपयोगिता तथा किसानों की आय वृद्धि के विभिन्न आयामों पर अपने विचार व्यक्त किए।

वक्ताओं ने कहा कि सहकारी समितियां ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। एफपीओ एवं पैक्स के प्रभावी संचालन से किसानों को बेहतर बाजार, संसाधन, तकनीकी मार्गदर्शन तथा आर्थिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे कृषि को अधिक लाभकारी एवं टिकाऊ बनाया जा सकता है।

कार्यक्रम में रासायनिक खेती के दुष्प्रभावों पर चर्चा करते हुए प्राकृतिक एवं जैविक खेती को अपनाने का आह्वान किया गया। साथ ही प्रत्येक सहकारी समिति द्वारा 3 जुलाई 2026 को कम से कम पांच पौधों

का रोपण कर उनके संरक्षण का संकल्प लेने की अपील की गई। वक्ताओं ने प्राकृतिक खेती को मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण एवं सतत कृषि विकास के लिए अत्यंत उपयोगी बताया।

संगोष्ठी में महिला नेतृत्व वाले एफपीओ एवं एफपीसी की भूमिका, उनके सफल संचालन तथा सदस्यों एवं संस्थाओं को प्राप्त होने वाले लाभों की जानकारी भी साझा की गई। सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री प्रदीप कुमार भालेकर ने प्राथमिक सहकारी समितियों के दैनिक कार्यों, दायित्वों एवं संचालन व्यवस्था पर विस्तार से प्रकाश डाला। कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों द्वारा सहकारिता, कृषि एवं बैंकिंग संबंधी विभिन्न विषयों पर प्रश्न पूछे गए, जिनका समाधान विभागीय अधिकारियों एवं बैंक प्रतिनिधियों द्वारा किया गया।

इस अवसर पर सहकारिता विभाग के प्रभारी सहकारिता विस्तार अधिकारी श्री आर.के. महिलांगे, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के अधिकारी-कर्मचारी, जिले की समस्त प्राथमिक कृषि साख सहकारी समितियों के प्राधिकृत अधिकारी एवं सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन श्री योगेन्द्र शर्मा, नोडल अधिकारी परिक्षेत्र खैरागढ़ द्वारा किया गया।

कलेक्टर ने दिखाई सख्ती : शासन की योजनाओं का लाभ हर पात्र हितग्राही तक पहुंचे

नई दृष्टिबिंदु / बेमेतरा

कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगाईं ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा (टीएल) बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, जनकल्याणकारी कार्यक्रमों, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, सुशासन तिहार के आवेदनों तथा विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट संदेश दिया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक योजना का लाभ समय पर पात्र हितग्राहियों तक पहुंचना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासन की सफलता योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और आम नागरिकों की संतुष्टि से तय होती है। इसलिए सभी अधिकारी जवाबदेही के साथ कार्य करें तथा निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर लापरवाही, अनावश्यक विलंब या उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारी-कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

धरातल पर दिखाई दे शासन की योजनाओं का प्रभाव : कलेक्टर ने कहा कि शासन की

जनकल्याणकारी योजनाओं का उद्देश्य केवल लक्ष्य पूरा करना नहीं, बल्कि आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। उन्होंने राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन सहित विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक विभाग निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य करते हुए योजनाओं का लाभ समय पर हितग्राहियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करे। उन्होंने कहा कि योजनाओं की सफलता का मूल्यांकन केवल आंकड़ों से नहीं, बल्कि धरातल पर दिखाई देने वाले परिणामों से होगा।

सुशासन तिहार के आवेदनों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निराकरण करें : बैठक में सुशासन तिहार के दौरान प्राप्त आवेदनों की भी समीक्षा की गई। कलेक्टर ने कहा कि यह अभियान शासन और आम नागरिकों के बीच विश्वास को मजबूत करने का माध्यम है। इसलिए प्रत्येक आवेदन का पारदर्शी, प्रभावी एवं स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित आवेदनों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण कर पात्र हितग्राहियों को शीघ्र लाभान्वित किया जाए तथा निराकरण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए।

ई-ऑफिस के माध्यम से बढ़े पारदर्शिता और कार्यकुशलता : कलेक्टर ने कार्यालयीन कार्यों में ई-ऑफिस प्रणाली के अधिकतम उपयोग पर जोर देते हुए कहा कि डिजिटल व्यवस्था से कार्यों में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं गति आएगी। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि फाइल संचालन, पत्राचार एवं अनुमोदन की प्रक्रिया नियमित रूप से ई-ऑफिस के माध्यम से संचालित की जाए। जिन विभागों में इसका उपयोग अपेक्षाकृत कम है, वे तत्काल सुधारात्मक कदम उठाएं।

टीएल प्रकरणों के निराकरण में गुणवत्ता से न करें समझौता : कलेक्टर ने कहा कि समय-सीमा (टीएल) के प्रकरणों का निराकरण पूरी गंभीरता एवं गुणवत्ता के साथ किया जाए। किसी भी प्रकरण का निपटारा केवल औपचारिकता के लिए न किया जाए। प्रत्येक विभाग यह सुनिश्चित करे कि आवेदकों को वास्तविक, संतोषजनक एवं स्थायी समाधान प्राप्त हो। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकतानुसार नियमित फील्ड विजिट कर योजनाओं एवं कार्यों की प्रगति का स्वयं निरीक्षण करें तथा समस्याओं का मौके पर समाधान सुनिश्चित करें। बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अपर कलेक्टर, सभी अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जिला स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का हो वास्तविक व स्थायी समाधान

बैठक में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के लंबित एवं निराकृत प्रकरणों की विभागवार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का निराकरण केवल पोर्टल पर प्रकरण बंद करने तक सीमित न रहे, बल्कि शिकायतकर्ता को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिकायतों के निराकरण की गुणवत्ता ही प्रशासन की कार्यप्रणाली का सबसे बड़ा पैमाना है। यदि किसी विभाग से बार-बार एक जैसी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं तो यह संबंधित विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार की आवश्यकता को दर्शाता है।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि प्रत्येक शिकायत का गंभीरतापूर्वक परीक्षण कर समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण एवं संतोषजनक निराकरण सुनिश्चित किया जाए। आवश्यक होने पर संबंधित अधिकारी स्वयं मौके पर जाकर वस्तुस्थिति का निरीक्षण करें और शिकायतों का स्थायी समाधान करें। निम्न रैंकिंग वाले विभागों को विशेष रूप से चेतावनी देते हुए आगामी समीक्षा बैठक तक उल्लेखनीय सुधार लाने के निर्देश दिए गए।

मुद्दे की बात

डॉ.सोनाली चक्रवर्ती के साथ

डिजिटल युग में बैनर पोस्टर की क्या उपयोगिता है ?

पूरे शहर, प्रदेश और देश की सुंदरता में सबसे बड़े दुश्मन है बिजली के खम्बो पर लगाए हुए पोस्टर बैनर और हर तरफ बड़े-बड़े होर्डिंग।

आश्चर्य इस बात का है कि जो जिम्मेदार है उन्हीं की तस्वीरों के पोस्टर से पूरा शहर अटा पड़ा है। पर्यावरण के सबसे बड़े दुश्मन है फ्लेक्स बैनर। फ्लेक्स बैनर पर्यावरण के लिए अत्यंत नुकसानदेह हैं। ये मुख्य रूप से पॉली-विनाइल क्लोराइड (पीवीसी) और रासायनिक प्लास्टिक से बनते हैं, जो न तो प्राकृतिक रूप से सड़ते हैं और न ही आसानी से रीसायकल होते है ।फ्लेक्स बैनर से पर्यावरण और स्वास्थ्य को होने वाले प्रमुख नुकसान ये है कि ये गैर-बायोडिग्रेडेबल फ्लेक्स बैनर सदियों तक पर्यावरण में ज्यों के त्यों पड़े रहते हैं।

इन्हें नष्ट करने के लिए अक्सर जला दिया जाता है, जिससे जहरीला कैंसरकारी और अत्यंत विषैली गैसें (जैसे कार्बन, सल्फेट, और नाइट्रेट) निकलती हैं जो हवा को दूषित करती है। जब ये कचरे के रूप में डंपिंग यार्ड में सड़ते हैं, तो इनमें मौजूद रसायन और प्लास्टिसाइजर रिस-रिसकर मिट्टी और भूजल को जहरीला बनाते है। ये जीव-जंतुओं के लिए भी अत्यंत नुकसानदेह हैं और अक्सर नालियों में फंसकर जलभराव जैसी समस्याएं पैदा करते हैं इन्हीं गंभीर प्रभावों को देखते हुए, भारत सरकार और कई राज्य सरकारों ने सरकारी आयोजनों में सिंगल-यूज या कम समय तक इस्तेमाल होने वाले पीवीसी फ्लेक्स बैनरों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है इसके बजाय कपड़े कागज या पर्यावरण-अनुकूल विकल्पों का उपयोग करने की सलाह दी जाती है जो कोई ना तो सुनता है ना मानता है।

हम बात करते हैं देश की स्वच्छता और पर्यावरण की सुरक्षा की लेकिन उसके लिए कोई काम नहीं करते। सिंगल यूज प्लास्टिक से हम लोगों को सावधान करते हैं लेकिन पूरे शहर भर में हर नेता के नाम के लगे हुए बैनर पोस्ट पर कोई बात नहीं करते। पहले केवल चुनावों में बैनर पोस्टर बनते थे परंतु अब वतर्मान हो या भूतपूर्व सभी नेताओं के जन्मदिन पर भी उनके समथर्कों द्वारा हजारों पोस्टर लगाने का चलन बढ़ गया है जिसने शहर की सुंदरता बिगाड़ रखी है। जन्मदिन बीतने के 6 महीने बाद भी उन पोस्टरों को निकाला नहीं जाता और वह गिर के,टूट के दुर्घटनाओं को निमंत्रण देते हैं।

हमारे देश में फ्लेक्स बैनर का चलन मुख्य रूप से 1998-1999 के आसपास शुरू हुआ ।इससे पहले भारत में विज्ञापनों और होर्डिंग्स के लिए मुख्य रूप से हाथ से पेंट किए गए कपड़े या लकड़ी-टीन के बोर्ड इस्तेमाल होते थे। बीसवीं सदी के अंत में जब भारत में डिजिटल लार्ज-फॉर्मेट प्रिंटिंग मशीनें आई, तब पीवीसी आधारित फ्लेक्स बैनर का इस्तेमाल व्यापक स्तर पर होने लगा ।शुरुआती दौर में प्रिंटिंग मशीनें और फ्लेक्स सामग्री विदेशों (जैसे चीन) से आयात किए जाते थे, लेकिन बाद में यह तकनीक पूरे देश में बहुत तेजी से फैली।

1990 से लेकर अब तक भारत में अरबों फ्लेक्स बैनर बनाए जा चुके हैं। भारत में भारतीय प्रिंटिंग उद्योग का पिछले तीन दशकों में तेजी से विस्तार हुआ है और फ्लेक्स, विज्ञापन, और आउटडोर प्रचार का सबसे सस्ता और प्रमुख माध्यम बन गया है। बिजली के पोल पर फ्लेक्स बैनर लगाना खतरनाक और गैर-कानूनी हो सकता है।

शॉर्ट सर्किट और आग का खतरा सबसे बड़ा है।

फ्लेक्स बैनर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक/पीवीसी और लोहे के तार बारिश या नमी के संपर्क में आकर बिजली के तारों से छू सकते हैं, जिससे शॉर्ट सर्किट और जानलेवा आग लगने का डर रहता है। यदि खंभे में कोई तकनीकी खराबी (अर्थिंग की समस्या) हो, तो फ्लेक्स लगाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के फ्रेम या तारों में करेंट आ सकता है, जिससे राहगीरों को जान का खतरा हो सकता है। भारी फ्लेक्स बैनर हवा में उड़ते हैं, जिससे खंभे पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। इससे खंभा झुक सकता है या टूट कर गिर सकता है, जिससे भारी नुकसान हो सकता है। बड़ा पोस्टर उड़ के कार की विंडस्क्रीन पर गिरकर कई दुर्घटनाएं हो भी चुकी है।

नगर निगम और बिजली विभाग के नियमों के अनुसार, बिजली के खंभों पर अनाधिकृत बैनर लगाना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर भारी जुर्माना और एफआईआर दर्ज होने का जोखिम रहता है। सड़क के मोड़ या चौराहों पर लगे बैनर ड्राइवरों को बाधित करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ जाती है। इस वर्ष भिलाई में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं। हर तरह के प्रदूषण से हमें जूझना होगा वायु से लेकर ध्वनि तक।

जब इस डिजिटल युग में हर किसी के हाथ में मोबाइल है तब हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए यह सबसे बड़ा साधन हो सकता है फिर बैनर पोस्टर की क्या जरूरत है ? प्रत्याशियों एवं नगर निगम द्वारा इस दिशा में उचित कदम उठाए जा सके तो यह एक प्रशंसनीय कार्य होगा। जापान में बिना किसी बैनर पोस्टर के चुनाव होता है हम उसका अनुसरण कर सकते हैं। आपके पास यदि कोई उपाय हो कि बिना बैनर पोस्टर और शहर की सुंदरता को बिगाड़े चुनाव कराया जा सके तो हमें जरूर बताइएगा।

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट

रायपुर। दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे छत्तीसगढ़ में एक्टिव हो गया है। पिछले 24 घंटों में सरगुजा और बस्तर के एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा हुई है। प्रदेश में आज और कल भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक, एक मौसमी द्रोणिक औसत समुद्र तल पर पांजब से बांगल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से तक फैली हुई है और औसत समुद्र तल से 0.9 किमी ऊपर तक फैली हुई है। बांगल की खाड़ी के उत्तरी हिस्से और उससे सटे दक्षिणी बांग्लादेश देश के ऊपर, औसत समुद्र तल से 1.5 से 7.6 किमी की ऊंचाई के बीच ऊपरी हवा में चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है, जो ऊंचाई के साथ दक्षिण-पश्चिम की ओर झुक रहा है। इसके प्रभव से 3 जुलाई 2026 के आसपास उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। उत्तर छत्तीसगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर, एक ऊपरी वायु चक्रवाती परिसंचरणा स्थित है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा बलरामपुर-रामानुजगंज में 34.7 डिग्री तापमान दर्ज किया गया।

दुर्ग के सब्जी बाजारों में चिल्हर की किल्लत दूर, व्यापारियों को बांटी गई चेंज

कलेक्टर के निर्देश पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से हुआ वितरण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग के फुटकर सब्जी बाजारों में चिल्हर की समस्या को दूर करने के लिए थोक फल सब्जी व्यापारी संगठन ने पहल की है। संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष नासिर खोखर ने इंदिरा मार्केट, समृद्धि बाजार, सिकोला बाजार और शनिचरी बाजार के फुटकर सब्जी विक्रेताओं को चिल्हर का वितरण किया।

व्यापार पर पड़ रहा था असर

नासिर खोखर ने बताया कि लगातार चिल्हर की किल्लत से व्यापारी परेशान थे। इससे उनके रोजाना के व्यापार पर भी असर पड़ रहा था। कई ऐसे विक्रेता हैं जो ऑनलाइन पेमेंट का उपयोग भी नहीं कर सकते। ग्राहकों को छुट्टे पैसे न दे पाने से बिक्री प्रभावित हो रही थी।

कलेक्टर से की थी मांग

इस समस्या को लेकर संगठन ने दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन देकर समाधान की मांग की थी। कलेक्टर के निर्देश पर बैंक ऑफ बड़ौदा के सहयोग से दुर्ग के चिल्हर सब्जी बाजारों में चेंज का वितरण किया गया। इससे छोटे व्यापारियों को बड़ी राहत मिली है।

GOSWWAMI
FLEX PRINTING
ADVERTIZER
भिलाई में सबसे सस्ता, सबसे अच्छा
Hoardings Flex Banner Vinyl Printing
One Way Vision Glow Sign Board
93290-13334, 74711-15735
goswamiflex@gmail.com
Address - 3rd Floor Shop No-1, Arora Tower, M.G. Market

अर्चना
फ्लाई ऐश ब्रिक्स
निर्माता एवं विक्रेता
हैवी इंडस्ट्रीयल एरिया, भिलाई
8 इंच एवं 9 इंच में उपलब्ध है।
संपर्क करें
9329960605, 9827160605, 9098639991

Baked by Suhani
Premium Homemade Cakes & Desserts
Birthday Cakes
Anniversary Cakes
Custom Theme Cakes
Serving Bhilai & Durg
baked.by.suhani
Suhani Singh
Premium Homemade Cakes & Desserts
Serving Bhilai & Durg
DM for Order
Followed by _s_andeep
Follow Message
Order Now:
@baked.by.suhani
M0.6263734520

10वीं, 12वीं, स्नातक एवं स्नातकोत्तर पास छात्र-छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण
नौकरी में सहायक
प्रवेश प्रारंभ सत्र 2026-2027
निजी कंपनियां जैसे पावर प्लांट, सीमेंट प्लांट, स्टील प्लांट, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत नौकरियाँ मिलती है।
प्रशिक्षण शुल्क में विशेष छूट
सरकारी मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र दिया जाएगा
फायर एवं सेफ्टी प्रशिक्षण में प्रवेश प्रारंभ

क्र.	पाठ्यक्रम का नाम	क्र.	पाठ्यक्रम का नाम
1.	फायर टेक्नोलॉजी एण्ड इंडस्ट्रियल सेफ्टी	5.	पी. जी. कोर्स व्यावसायिक सेफ्टी, स्वास्थ्य व पर्यावरण मैनेजमेंट सिस्टम
2.	इंडस्ट्रियल सेफ्टी / पी. जी. इंडस्ट्रियल सेफ्टी	6.	हैल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर
3.	बी.एस.सी. इन फायर सेफ्टी	7.	सब- फायर ऑफिसर
4.	पी. जी. कोर्स फायर एवं इंडस्ट्रियल सेफ्टी	8.	सर्टिफिकेट इन फायरमैन-इंडस्ट्रियल सेफ्टी

(An Authorized Training Centre of AEERO)
फायर सेफ्टी एवं डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट
(मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान)
कैंपस :- इंदिरा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, सुपेला, भिलाई, जिला-दुर्ग, छत्तीसगढ़
ADMISSION HELPLINE: 7697212782

BA
BCA
BCom
BBA
BSc
PGDCA
MSc CHEMISTRY
MSc BIOTECHNOLOGY
MSc BOTANY
MSc ZOOLOGY
MSc COMPUTER Sc
MSc MATHS
MA ENGLISH
MCom
BLib
MLib
DCA
MA CHHATTISGARHI
Affiliated to Hemchand Yadav University, Durg
SAI COLLEGE
Street-69, Sector-6, Bhilai
70248 86996
99770 01027
Deepak Advertisers

"यह समाचार पत्र आलोक तिवारी द्वारा 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से आलोक तिवारी की ओर से प्रकाशित की जाती है, जिसका संपादन आलोक तिवारी द्वारा किया जाता है तथा इसका मुद्रण समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 पर किया जाता है। (समाचार चयन के लिए PRP Act, 2023 के तहत संपादक जिम्मेदार है)। समस्त विवादों का निपटारा न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।" संपादक आलोक तिवारी, मो. 74154-69100